सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2021 | अंक 02

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी
जून ◉ 2021 | अंक ◉ 02

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

विषय सूची

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे	1-12
सप्ताह के चर्चित व्यक्ति	13-16
सप्ताह के चर्चित स्थान	17-21
सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस	22-26
ब्रेन बूस्टर	27-34
स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	35-39
स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न)	40-41

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)
- जी-7 देशों के बीच अहम समझौता
- 24वां बिम्सटेक दिवस
- ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति
- इंडिया इंडेक्स 2020-21
- विश्व बैंक
- LEO उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा
- नासा द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले दो नए मिशन की घोषणा
- आठवां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन
- श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव
- कोविड-19 का केवल डेल्टा वैरिएंट बेहद चिंताजनक : डबल्यूएचओ
- अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index- PGI) 2019-20 जारी की है।

मुख्य बिन्दु

- 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20' में तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा केरल को उच्चतम ग्रेड (A++) प्राप्त हुआ है।
- वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ज्यादातर राज्यों ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया है। यहां स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा गया है।
- 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20' में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की दस कैटेगरी बनाई गई हैं। इसकी पहली कैटेगरी में फिलहाल कोई राज्य नहीं आ सका है।
- 'पीजीआई 2019-20' की दूसरी कैटेगरी में पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
- 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20' के मुताबिक, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं।

ग्रेड	राज्य
ग्रेड I++	पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल
ग्रेड I+	गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, एनसीटी-दिल्ली, पुदुचेरी, राजस्थान, दादर और नगर हवेली
ग्रेड I	आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और दमन व दीव
ग्रेड II	गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्ष्यद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर
ग्रेड III	असम, बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम
ग्रेड IV	अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड
ग्रेड V	मेघालय
ग्रेड VI	-
ग्रेड VII	लद्दाख

क्या है 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स'

- 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा क्षेत्र में परफॉरमेंस के जाँचने हेतु जारी किया जाता है। इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 'स्कूली शिक्षा' के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर ग्रेडिंग की गई है। इन 70 संकेतकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है-

  - प्रथम- परिणाम और प्रशासन,
  - द्वितीय- प्रबंधन।
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' (PGI) को पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किया गया 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20', भारत में स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन से जुड़ी तीसरी रिपोर्ट है।

लाभ

- 'परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' (PGI) से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा क्षेत्र में अपनी कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलाईजेशन लाने हेतु भी प्रोत्साहित करता है।

2. जी-7 देशों के बीच अहम समझौता

चर्चा का कारण

- हाल ही में जी-7 के देशों के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। इस समझौते से प्रौद्योगिकी कंपनियों को उचित कर का भुगतान करना होगा।

मुख्य बिन्दु

- जी-7 समूह के देशों ने कर अपवंचना से बचाव के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां उचित तरीके से अपने हिस्से के कर का भुगतान करेंगी।
- यह समूह सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 15 फीसदी वैश्विक न्यूनतम कर दर पर सहमत हुआ है।
- जी-7 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों ने लंदन में बैठक के दौरान इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कई वर्षों के विचार-विमर्श के बाद जी-7 समूह के देशों के बीच वैश्विक कराधान प्रणाली में सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी कंपनियां सही स्थान पर सही कर का भुगतान करें।
- उल्लेखनीय है कि यह समझौता जी-7 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन में वैश्विक संधि का आधार बन सकता है।

जी-7 समूह के बारे में

- जी-7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) भी कहते हैं।
- जी-7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। विदित हो कि कनाडा 1976 में इस समूह में शामिल हुआ था।
- शुरुआत से ही आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित, जी -7 फोरम ने दशकों से कई चुनौतियों के बारे में विचार-विमर्श किया है, जैसे कि 1970 के दशक में तेल संकट, वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि।
- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक जी-7 को जी-8 के रूप में जाना जाता था, किन्तु वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुनः जी-7 कहा जाने लगा।
- जी-7 का औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं।

जी-7 की आलोचना

- जी-7 की आलोचना यह कह कर की जाती है कि यह समूह अभी तक बहुत ज्यादा प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि यह समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना आदि भी शामिल है।
- समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक करोड़ों लोगों की जान बचाई है।
- समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- जी-7 समूह का कहना है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में उसने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जबकि आलोचकों का इसके विपरीत मत है।

3. 24वां बिम्सटेक दिवस

चर्चा का कारण

- हाल ही में 24वां बिम्सटेक दिवस (24th BIMSTEC Day) मनाया गया है। वर्तमान में बिम्सटेक की अध्यक्षता श्रीलंका कर रहा है।

मुख्य बिन्दु

- 24वें बिम्सटेक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्सटेक (BIMSTEC) समूह आगे बढ़ रहा है और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बंगाल की खाड़ी के निर्माण के साझा सहयोग की नई ऊंचाइयां छू रहा है।
- उन्होंने वर्तमान में बिम्सटेक की अध्यक्षता कर रहे श्रीलंका की सराहना करते हुए कहा कि इस देश ने ऐसी कठिन परिस्थिति में समूह को कुशल नेतृत्व दिया है।
- बिम्सटेक (BIMSTEC), एक भरोसा जगाने वाले क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है। इस समूह ने संपर्क के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने सहित कई मोर्चों पर प्रगति की है।
- बिम्सटेक समूह ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलकर जीत हासिल करने पर जोर दिया है।
- इसके अलावा, बिम्सटेक ढांचे में क्षेत्रीय सहयोग हाल के दिनों में बढ़ा है।

बिम्सटेक (BIMSTEC)

- इसका पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन' (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC) है।
- बिम्सटेक (BIMSTEC) में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार सदस्य हैं।

- बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC)] बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और समीपवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय ढाका में अवस्थित है।
- गौरतलब है कि एक उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में इसका गठन 6 जून, 1997 को बैंकाक घोषणा के बाद किया गया था।
- शुरू में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे तब इसका नाम 'BISTEC' यानि 'बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन' था। दिसंबर 1997 में म्यांमार भी इस समूह से जुड़ गया और इसका नाम बिम्सटेक पड़ा। इसके बाद फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी समूह में शामिल हो गए।
- बिम्सटेक (BIMSTEC), सदस्य देशों के बीच आपसी बातचीत के लिये उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करता है। शिखर सम्मेलनों, मध्य स्तरीय बैठकों, उच्चाधिकारियों की बैठकों और विशेषज्ञों के बीच वार्ताओं के अलावा बैंकाक स्थित बिम्सटेक वर्किंग ग्रुप के द्वारा यह विभिन्न सरकारों के बीच संपर्क स्थापित करने का मंच मुहैया कराता है।

बिम्सटेक (BIMSTEC) का महत्व

- बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। दुनिया की आबादी का 1/5 भाग (22%) इसके आसपास के सात देशों में रहता है। बंगाल की खाड़ी में विशाल अप्रयुक्त (बिना इस्तेमाल हुए) प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। विश्व का एक चौथाई व्यापार बंगाल की खाड़ी के जरिए होता है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बिम्सटेक (BIMSTEC)?

- आशियान देशों के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए बिम्सटेक बेहतर जरिया है।बिम्सटेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी तंत्र को भी जोड़ता है।भारत की विदेश नीति की केंद्रीय बिंदु 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए बिम्सटेक एक प्राकृतिक मंच है। भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की की अपार संभावना है। लगभग 300 मिलियन लोग बंगाल की खाड़ी (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) से सटे चार तटीय राज्यों में रहते हैं। इसके साथ ही लगभग 45 मिलियन लोग पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। यदि ये दोनों क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए संभावना के द्वार खुल जाएंगे।
- सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) से जुडी बंगाल की खाड़ी, चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुँच सुनिश्चित करने में एक प्रमुख आधार बन गया है।चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चला रखा है। चीन का बंगाल की खाड़ी में आक्रामक गतिविधियां और हिंद महासागर में सबमरीन/ पनडुब्बियों के आवागमन बढ़ने से उत्पन्न चुनौतियों को प्रति संतुलित करने के लिए भारत को बिम्सटेक देशों के मध्य आंतरिक संबंध को बढ़ाना होगा।

4. ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ

चर्चा का कारण

- हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ मनाई गई। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। यह दावा ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टीनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड ने अपनी किताब 'ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच' में किया है।

क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार?

- भारतीय सेना की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर कि गई कार्यवाही को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से जाना जाता है। जून 1984 की घटना के बाद से हर साल यहां 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ मनाई जाती है। 5 जून, 1984 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिये भारतीय सैन्य अभियान को दिया गया एक कोड नाम है। ऑपरेशन मुख्य रूप से अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर पर नियंत्रण करने के लिये दिया था। सिख चरमपंथी धार्मिक नेता, जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को इस परिसर में बाहर निकालने के लिये भारतीय सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया।
- इस ऑपरेशन के मुख्यत: दो घटक थे–
  - **प्रथम:** ऑपरेशन मेटल जो कि मंदिर परिसर पर आक्रमण था।
  - **द्वितीय:** ऑपरेशन शॉप (Operation Shop) जो राज्य के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था।
- इस ऑपरेशन ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की। इसके परिणामस्वरूप भिंडरावाले की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली में गंभीर सिख विरोधी दंगे हुए थे।

पृष्ठभूमि

- पंजाब समस्या की शुरुआत 1970 के दशक से अकाली राजनीति में खींचतान और अकालियों की पंजाब संबंधित माँगों के रूप में हुई थी। 1973 और 1978 ई. में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मूल प्रस्ताव में सुझाया गया था कि भारत की केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो जबकि अन्य विषयों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार हों। वे भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्वायत्तता चाहते थे। उनकी माँग थी कि- चंडीगढ़ केवल पंजाब की ही राजधानी हो, पंजाबी भाषी क्षेत्र

पंजाब में शामिल किए जाएँ, नदियों के पानी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाए, 'नहरों के हेडवर्क्स' और पन-बिजली बनाने के मूलभूत ढाँचे का प्रबंधन पंजाब के पास हो, फौज में भर्ती काबिलियत के आधार पर हो और इसमें सिखों की भर्ती पर लगी कथित सीमा हटाई जाए, तथा अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाया जाए।

- इसके अलावा जरनैल सिंह भिंडरावाले चाहते थे कि भारत सरकार आनंदपुर प्रस्ताव पारित करे और इस तरह सिखों के लिये एक अलग खालिस्तान राज्य के गठन के लिये सहमत हो। वर्ष 1982 के बाद से सिख धर्म के इस कट्टरपंथी नेता ने अपने कार्य के लिये पर्याप्त समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की और वर्ष 1983 के मध्य तक गोला-बारूद तथा अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर एक आधार स्थापित कर लिया था। इसलिये भिंडरावाले और उनकी मांगों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से 1 जून और 6 जून, 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- यह एक आतंकवाद-रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986' द्वारा अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय मानेसर, गुरुग्राम में स्थित है। आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिये आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने को ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस तरह के बल को बनाने का विचार आया।

5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि एक अप्रैल 2020 से पांच जून 2021 के बीच देश में कोविड-19 महामारी से 3621 बच्चे अनाथ हो गए हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को, महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी बाल स्वराज पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिन्दु

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशभर के बाल संरक्षण केंद्रों में 274 बच्चे परित्यक्त मिले हैं। इन्हें मिलाकर पोर्टल पर कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या 30,071 है।
- आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी एकत्र करने के बाद 'बाल स्वराज' पोर्टल पर बच्चों को पंजीकृत किया है।
- 'बाल स्वराज' पोर्टल का विवरण दिखाता है कि देश में लगभग 10,000 बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। इनमें मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान, 0 से 17 वर्ष तक की आयु के अनाथ या परित्यक्त बच्चे शामिल हैं।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि इन बच्चों को तस्करी और देह व्यापार में धकेले जाने का जाने का खतरा काफी अधिक है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005, के तहत एक सांवैधानिक निकाय के रूप में की गई।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़े सभी नीतियों में अत्यावश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है।

आयोग का गठन

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ होना आवश्यक है।
- केंद्र सरकार द्वारा आयोग में निम्नलिखित सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा।
- अध्यक्ष, जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- छह अन्य सदस्य जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय, हाशिये पर पड़े उपेक्षित, अपंग व परित्यक्त बच्चों की देखभाल या बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो।
- सदस्य सचिव, जो संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष होगा या उसके नीचे स्तर का नहीं होगा।

आयोग की शक्तियां

- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए उस समय प्रचलित किसी कानून के तहत या दिए गए बचाव की जांच और समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।
- इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केन्द्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
- उक्त मामलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और कार्यवाही चलाने की सिफारिश करना।
- उन सभी कारकों की जांच करना जो आंतकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगो, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, अनैतिक व्यापार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चित्रण, तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावित बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर विचार करना, जिसमें तनाव युक्त, उपेक्षित और लाभ वंचित बच्चे, कानून के साथ विवाद रखने वाले बच्चे, किशोर, परिवार के बिना रहने वाले बच्चे और कैदियों के बच्चे शामिल हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और साधनों का अध्ययन करना तथा मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने मौद्रिक नीति (Monetary Policy) जारी की है।

मौद्रिक नीति के प्रमुख बिन्दु

- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए आरबीआई एकोमोडेटिव स्टांस को बरकरार रखेगा।
- इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए 10.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2021-22 में खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान भी लगाया है।
- वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौजूदा दरें निम्नलिखित हैं-
  - रेपो रेट - 4.00%
  - रिवर्स रेपो रेट - 3.35%
  - मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट - 4.25%
  - बैंक रेट - 4.25%

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC)

- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया था। इस प्रकार यह एक सांविधानिक निकाय है।
- भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) में निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं और समान मतों की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।
- मौद्रिक नीति समिति एक छह सदस्यीय समिति होती है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था।
- इसमें तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं।
- आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है।
- इस समीक्षा में अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है।
- दूसरे शब्दों में कहें तो मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करती है।
- वहीं राजकोषीय नीति के जरिए सरकार द्वारा समग्र मांग और अर्थव्यवस्था पर सरकारी खर्च और करों के असर को नियंत्रित किया जाता है।

मौद्रिक नीति समीक्षा का उद्देश्य?

- मौद्रिक नीति से कई मकसद साधे जाते हैं। इनमें महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। इसके अलावा, रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके लक्ष्यों में से एक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) देश का केन्द्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 के तहत 5 करोड़ रूपए की शुरूआती धनराशि के साथ की गई थी, बाद में, कुछ सीमित लोगों के हाथों में शेयरों के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

- भारतीय रिजर्व बैंक के कई प्रमुख कार्य हैं जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करना, उसको लागू करना और उसकी निगरानी करना; वित्तीय प्रणाली का रेगुलेशन और निगरानी करना; विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन करना; मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना इत्यादि।इसके अलावा, आरबीआई साख नियन्त्रित करने और मुद्रा के लेन-देन को नियंत्रित करने का कार्य तथा सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में भी काम करती है।भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करती है।

2. इंडिया इंडेक्स 2020-21

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal - SDG) सूचकांक जारी किया है।

सूचकांक के नवीनतम निष्कर्ष

- देश के स्तर पर एसडीजी स्कोर 2020-21 में छह अंकों के सुधार के साथ 60 से बढ़कर 66 अंक रहा है।
- केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला।
- इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंड़ीगढ़ शीर्ष पर रहा, जिसके बाद 68 अंक के साथ दिल्ली का स्थान रहा।
- वर्ष 2020-21 में अपने स्कोर को बेहतर बनाने में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड सबसे आगे रहे। उनके आंकड़े में क्रमश: 12, 10 और आठ अंक का सुधार हुआ।
- जहां 2019 में 65 से 99 अंक का स्कोर हासिल करने वाले सबसे आगे रहने वाले राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में 10 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे, वहीं इस बार इसमें 12 और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने इसमें जगह बनाई है।
- उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने 65 से 99 अंक के दायरे में स्कोर हासिल कर दौड़ में आगे रहने वाले राज्यों का स्थान प्राप्त किया।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लक्ष्यों के लिहाज से गुजरात और दिल्ली क्रमश: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर रहे।
- वहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों श्रेणियों में क्रमश: केरल और चंडीगढ़ सबसे ऊपर रहे। गरीबी नहीं (नो पॉवर्टी) लक्ष्य के तहत तमिलनाडु और दिल्ली शीर्ष पर थे। विषमताओं में कमी के मामले में मेघालय और चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों को 100 अंक मिले।

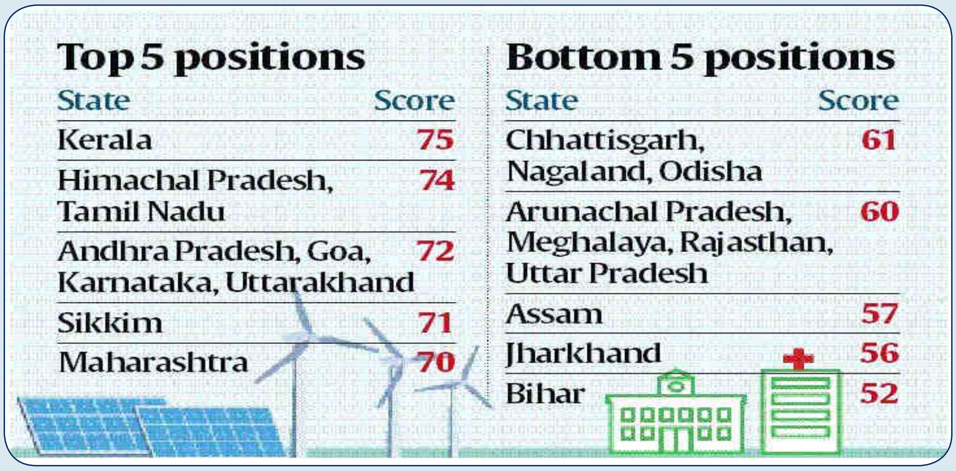

Top 5 positions

State	Score
Kerala	75
Himachal Pradesh, Tamil Nadu	74
Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand	72
Sikkim	71
Maharashtra	70

Bottom 5 positions

State	Score
Chhattisgarh, Nagaland, Odisha	61
Arunachal Pradesh, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh	60
Assam	57
Jharkhand	56
Bihar	52

सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स क्या है ?

- नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की भारतीय शाखा के साथ मिलकर 2018 में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स की शुरुआत की थी।
- इस इंडेक्स को सतत विकास लक्ष्य के 16 लक्ष्यों को पैमाना बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें गरीबी निवारण, भूख को खत्म करना, स्वास्थ्य और लोगों का कल्याण, शिक्षा की गुणवत्ता, साफ पानी और सफाई, साफ ऊर्जा और लिंग समानता जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
- भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतकों पर आंकता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) से जुड़े हैं।
- यह सूचकांक वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अब तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है और यह स्थायित्व, दृढ़ता और सहयोग के संदेश को आगे बढ़ाने में सफल रहा है।
- पहले संस्करण 2018-19 में 13 उद्देश्य, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था, जबकि इस तीसरे संस्करण में 17 ध्येय, 70 लक्ष्यों और 115 संकेतकों को शामिल किया गया।

कार्यप्रणाली और प्रक्रिया

- सूचकांक का निर्माण और आगामी कार्यप्रणाली एसडीजी पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने और उन्हें रैंकिंग देने के केंद्रीय उद्देश्यों का प्रतीक है; ये उन क्षेत्रों की पहचान करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करता है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है; और यह उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- सूचकांक अनुमान 17 उद्देश्यों के गुणात्मक मूल्यांकन के साथ पहले 16 उद्देश्यों के लिए संकेतकों से संबंधित डेटा पर आधारित है। लक्ष्य निर्धारण और अंक के सामान्यीकरण की तकनीकी प्रक्रिया विश्व स्तर पर स्थापित पद्धति का पालन करती है।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर, 0-100 के बीच होते हैं। राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है:
  - प्रतियोगी (Aspirant): 0-49
  - प्रदर्शन करने वाला (Performer): 50-64
  - सबसे आगे चलने वाला (Front-Runner): 65-99
  - लक्ष्य हासिल करने वाला (Achiever): 100

3. ब्लैक कार्बन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व बैंक ने अपने एक अहम अध्ययन में कहा है कि 'ब्लैक कार्बन' (black carbon) बढ़ने से संवेदनशील हिमालयी श्रृंखला में हिमनद और बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। इसके साथ ही तापमान बदल रहा है तथा बारिश की प्रवृत्ति (पैटर्न) बदल रही है।

प्रमुख बिन्दु

- विश्व बैंक की इस शोध रिपोर्ट का शीर्षक "हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन" (Glaciers of the Himalayas, Climate Change, Black Carbon and Regional Resilience) है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- मानव गतिविधि द्वारा उत्पादित ब्लैक कार्बन हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और बर्फ के पिघलने की गति को तेज करता है।
- विश्व बैंक की शोध में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश (Himalaya, Karakoram and Hindu-Kush) पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया है जहां पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव देखा जा सकता है। इन पर्वत श्रंखलाओं में हिमनदों के पिघलने के गति, विश्व के औसत हिमक्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।
- हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश ग्लेशियरों के पीछे हटने की दर पश्चिम में प्रति वर्ष 0.3 मीटर और पूर्व में 1.0 मीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान है।
- ब्लैक कार्बन (Black Carbon) को कम करने हेतु मौजूदा नीतियों के पूर्ण कार्यान्वयन से हिमनदों के पिघलने के गति में 23% की कमी हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त नई तथा वर्तमान में व्यवहार्य नीतियों के माध्यम से ग्लेशियरों के पीछे हटने की दर को 50% तक अधिक तेजी से कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पहाड़ों में लगभग 55000 हिमनद हैं, और वे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाहर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक मीठे पानी का भंडारण करते हैं।

ब्लैक कार्बन

- ब्लैक कार्बन दरअसल जीवाश्व और अन्य जैव ईंधनों के अपूर्ण दहन की वजह से उत्सर्जित कणिकीय पदार्थ (पर्टिकुलेटेड मैटर) हैं, जो वायुमंडल का ताप बढ़ाते हैं।
- यह दक्षिण एशिया के अंदर और बाहर मानवीय गतिविधियों से पैदा होता है। यह हवा में मौजूद कणों का बड़ा हिस्सा है जो जलवायु परिवर्तन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के बाद ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक ब्लैक कार्बन (BC) ही है।

ब्लैक कार्बन में कटौती करना जरूरी

- मानवजनित द्वारा ब्लैक कार्बन जमाव में, उद्योग (मुख्य रूप से ईंट भट्टों) और स्थानीय निवासियों द्वारा ठोस ईंधन के दहन का 45-66% योगदान होता है, इसके बाद परिवहन वाहनों द्वारा डीजल ईंधन (7-18%) और खुले में दहन (3% से कम) का योगदान होता है।
- ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए चल रहे कुछ नीतिगत उपायों में वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानकों को बढ़ाना, डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, खाना पकाने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग में तेजी लाना और स्वच्छ चूल्हे के कार्यक्रमों के साथ-साथ ईंट भट्ठा प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करना शामिल है।
- ब्लैक कार्बन पर मजबूत नीतियां ग्लेशियर के पिघलने में तेजी से कटौती कर सकती हैं।

4. LEO उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा

चर्चा का कारण

- एक प्रमुख सैटेलाइट कंसल्टेंसी फर्म यूरोकंसल्ट (Euroconsult) का अनुमान है कि इस दशक में सालाना 1,250 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें से 70% वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए होंगे।

LEO प्रोद्योगिकी एवं सैटेलाइट इंटरनेट

- LEO उपग्रह 1990 के दशक से ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, ये कंपनियों और व्यक्तियों को विभिन्न संचार सेवाएं प्रदान करते हैं।
- जियोस्टेशनरी उपग्रह धरती की भूमध्यरेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होते हैं यह बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। इनकी तुलना में LEO उपग्रह पृथ्वी से लगभग 500km-2000km स्थित हैं।
- चूंकि LEO उपग्रह पृथ्वी के करीब परिक्रमा करते हैं, वे पारंपरिक स्थिर-उपग्रह प्रणालियों की तुलना में मजबूत सिग्नल और तीव्र गति प्रदान करने में सक्षम हैं।
- इसके अतिरिक्त, सिग्नल फाइबर-ऑप्टिक केबल की तुलना में ये अंतरिक्ष के माध्यम से तीव्र गति से चलते हैं।

चुनौतियाँ

- LEO उपग्रह 27,000 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं और 90-120 मिनट में पृथ्वी का एक पूर्ण परिपथ पूरा कर लेते हैं। नतीजतन, एक उपग्रह पृथ्वी पर स्थापित ट्रांसमीटर के साथ बहुत कम समय लिए संपर्क स्थापित कर पाता है, ऐसे में बड़े पैमाने पर एलईओ उपग्रह बेड़े की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है।

- विशेषज्ञों का मानना है कि LEO सैटेलाइट ब्रॉडबैंड केवल उन क्षेत्रों में बेहतर है जहां फाइबर और स्पेक्ट्रम सेवाओं तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

LEO उपग्रहों से जुड़ी समस्याएँ

- अंतरिक्ष में हजारों उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में साजो-सामान संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। उपग्रहों को कभी-कभी रात के वक्त खुले आसमान में देखा जा सकता है जो खगोलविदों के लिए मुश्किलें पैदा करता है क्योंकि उपग्रह पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं, जिससे छवियों में लकीरें एक दूसरे के पार दिखाई देती हैं।
- निचली कक्षा में यात्रा करने वाले उपग्रह अपने ऊपर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की आवृत्ति को भी बाधित कर सकते हैं।
- एक और चिंता की बात यह है कि कक्षा में पहले से ही 1cm व्यास से बड़ी लगभग 1 मिलियन वस्तुएं हैं, जो दशकों की अंतरिक्ष गतिविधियों का उपोत्पाद है। उन वस्तुओं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में 'अंतरिक्ष कबाड़' कहा जाता है, में अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाने या अन्य उपग्रहों से टकराने की क्षमता होती है।

भारतीय उपग्रह इंटरनेट बाजार

- वर्तमान में स्टारलिंक (Starlink एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के नेतृत्व वाला एक उद्यम है।) और वनवेब (OneWeb एक निजी कंपनी है जिसने LEO में 218 उपग्रहों के तारामंडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।) का लक्ष्य 2022 तक भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लॉन्च करना है, साथ ही अमेजॅन के प्रोजेक्ट कुइपर (Kuiper) भी देश में काम करने के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह वर्ष 2019 में शुरू की गई अमेजन (Amazon) की एक परियोजना है।

संभावित लाभ

- भारत में 70% से अधिक ग्रामीण भारतीयों के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है, ऐसे में जिन स्थानों पर फाइबर और स्पेक्ट्रम सेवाओं की पहुँच नहीं होती है, वहां LEO सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेहतर कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के आलोक में शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण आवश्यकता महसूस की जा रही है।

5. नासा का शुक्र मिशन

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दो नए मिशनों की घोषणा की है। ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन 2028 से 2030 के बीच शुरू किए जाएंगे।

उद्देश्य

- इन दो मिशनों का उद्देश्य यह समझना है कि शुक्र की तरह कैसे इतनी ज्यादा गर्म है।
- शुक्र ग्रह का इतिहास, ग्रीनहाउस प्रभाव को पढ़ने और धरती पर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, यह समझने का बेहतरीन मौका उपलब्ध कराएगा। इसके लिए ऐसे मॉडलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें शुक्र के वायुमंडल की चरम स्थितियों को तैयार किया जा सकता है और परिणामों की तुलना धरती पर मौजूदा स्थितियों से कर सकते हैं।

दविंची+ (Davinci+)

- दविंची+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases] Chemistry and Imaging- DAVINCI+) शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करेगा। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या शुक्र पर कोई समुद्र भी था।
- दविंची+ शुक्र के तीव्र ग्रीनहाउस गैसों के कारणों का पता लगाने की कोशिश करने के लिए ग्रह के तत्वों को मापेगा।

वेरिटास

- वेरिटास शुक्र की सतह पर कठोर चट्टान के नमूने प्राप्त करके इस पड़ोसी ग्रह के भूवैज्ञानिक विज्ञान को समझने में मदद करेगा। इसके जरिए यह समझने में मदद मिल सकती है कि यह ग्रह कैसे बना।
- वेरिटास' वीनस एमिशिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का संक्षिप्त रूप है। यह और ऊंचे मानक वाला ग्रह मिशन होगा। ऑर्बिटर अपने साथ दो उपकरण ले जाएगा जिनकी मदद से सतह का मानचित्र तैयार किया जाएगा और दाविंची से मिले विस्तृत इन्फ्रारेड अवलोकनों का पूरक होगा।

दो उपकरण होंगे

- इसका पहला उपकरण विभिन्न रेडियो तरंगों की सीमाओं को देखने वाला कैमरा होगा। यह शुक्र ग्रह के बादलों के पार तक देख सकता है जिससे वायुमंडलीय एवं मैदानी संरचना की जांच हो सकेगी।
- दूसरा उपकरण रडार है और यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों पर अत्यधिक इस्तेमाल होने वाली तकनीक का प्रयोग करेगा। उच्च रेजॉल्यूशन वाली रडार छवियां और अधिक विस्तृत मानचित्र पैदा करेगा जो शुक्र के सतह की उत्पत्ति की जांच करेगी।

शुक्र ग्रह

- समान आकार और संरचना के कारण शुक्र को अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं।
- शुक्र ग्रह पर कार्बन खिसककर वातावरण में चला गया है जिससे इसके वातावरण में तकरीबन 96 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड है। इससे बहुत ही तेज ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न हुआ जिससे सतह का तापमान 750 केल्विन (470 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री फॉरेनहाइट) तक चला गया है।
- यहां का अधिकतम तापमान 90 बार जितने उच्च दबाव जितना है (तकरीबन एक किलोमीटर नीचे के पानी के प्रवाह जितना)। यह दबाव इतना है जो तत्काल अधिकांश लैंडरों को नष्ट कर सकता है। ध्यातव्य है कि शुक्र तक अब तक गए मिशन योजना के मुताबिक नहीं रहे हैं।

6. आठवां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन

चर्चा का कारण

- हाल ही में आठवें 'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन' (International Nitrogen Initiative Conference- INI2020), का आयोजन जर्मनी में आभासी-प्रारूप में किया गया। इस सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के 800 से अधिक वैज्ञानिक और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन

- अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल (International Nitrogen Initiative-INI) एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे 2003 में पर्यावरण की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति (SCOPE) और अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल-जैवमंडल कार्यक्रम (International Geosphere-Biosphere Program -IGBP) के प्रायोजन के तहत स्थापित किया गया था।
- आईएनआई का समन्वय एक संचालन समिति द्वारा किया जाता है, जिसके नेतृत्व में एक अध्यक्ष और छह क्षेत्रीय केंद्र निदेशक होते हैं, जो अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया से चुने जाते हैं।
- आईएनआई हर तीन साल में एक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा नाइट्रोजन मुद्दों पर ज्ञान का आदान-प्रदान किया जाता है।

आईएनआई के प्रमुख उद्देश्य

- टिकाऊ खाद्य उत्पादन में नाइट्रोजन की फायदेमंद भूमिका को अनुकूलित करना।
- खाद्य और ऊर्जा उत्पादन के दौरान मानव स्वास्थ्य पर नाइट्रोजन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।

नाइट्रोजन गैस

- नाइट्रोजन (Nitrogen), भूयाति या नत्रजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक छ है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। पृथ्वी के वायुमण्डल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैण्ड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी।
- नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है जो जीव द्रव्य का अभिन्न अंग है तथा पर्ण हरित के निर्माण में भी भाग लेती है। नाइट्रोजन का पौधों की वृद्धि एवं विकास में योगदान देते हैं।
- प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कार्य अनेक साधनों द्वारा होता है। भूमि के अनेक जीवाणु, जैसे एजोटोबैक्टर (Azotobacter) तथा कुछ पौधों की जड़ों में स्थित जीवाणु, जैसे राइजोवियम (Rhizobium), इस कार्य को सदैव करते रहते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अनेक प्रक्रम ज्ञात है। इनमें से एक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें ऊष्माशोषी (endothermic) क्रिया होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन (Reactive nitrogen) में अमोनिया, अमोनियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रेट एवं यूरिया, अमाइन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड जैसे जैविक यौगिक शामिल हैं।

7. श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में सिंगापुर के MVX -प्रेस पर्ल (MV X-Press Pearl) नामक मालवाहक जहाज में आग लगने और विस्फोट होने से श्रीलंका के समुद्र तटों पर कई टन प्लास्टिक के पैलेट (pellet) पाए गए।

प्रमुख बिन्दु

- प्लास्टिक कचरे से भरे जहाज के जलने के बाद उसके अवशेष बहकर उसके द्वीपों पर पहुंच रहे हैं और जल-जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। इसके अतिरिक्त ये जलवायु के लिए बेहद खतरनाक हैं और हिंद महासागर के जल जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- पर्यावरण कर्मियों को चिंता है कि यह कचरा मैंग्रोव और उथले पानी में पैदा होने वाली मछलियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। समुद्र तट के नजदीक कोरल भी खतरे में हैं। जहाज में 278 टन तेल और 50 टन डीजल था जिसके लीक होने से खतरा और बढ़ जाएगा।

समुद्री तेल रिसाव

- समुद्री प्रदूषण का प्रमुख कारण तेल रिसाव है। यह मानवीय और प्राकृतिक, दोनों ही प्रकार से हो सकता है; हालांकि यह मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के कारण ही होता है जो कभी-कभी भयानक रूप ले लेता है।
- इस प्रकार समुद्री तेल रिसाव, एक प्रकार का प्रदूषण है; जिसमें मानवीय व प्राकृतिक गतिविधियों के कारण तरल पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन (यथा- कच्चा तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद व उनके उप-उत्पाद ,बेड़े में प्रयुक्त होने वाले भारी ईंधन जैसे बंकर ईंधन, तैलीय अवशिष्ट या अपशिष्ट तेल आदि) समुद्री पर्यावरण (यथा- तटीय क्षेत्र आदि) में मुक्त हो जाता है।
- पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन का रिसाव मुख्यतः टैंकर, अपतटीय प्लेटफार्म , खुदाई उपकरण, जहाज, तेल के कुओं इत्यादि से होता है।

समुद्री तेल रिसाव के नुकसान

- समुद्री या तटीय प्रदूषण के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण आदि

सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- समुद्री तेल रिसाव का नुकसान सिर्फ समुद्री जीवों और वन्यजीवों तक सीमित नहीं है। तेल के रिसाव से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का आवास और जनजीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तेल से लथपथ समुद्री जीवों को अगर मानव सेवन कर ले तो उसका शरीर बीमारियों का घर बन सकता है।
- समुद्र में बड़े पैमाने पर फैले तेल से छुटकारा पाने के लिए जब पानी पर तैर रहे तेल के कुछ हिस्सों को आग लगाई जाती है तो इससे वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोआक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होकर वायुमंडल मे प्रवेश कर जाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग आदि का कारण बनती हैं।
- तेल की चिकनाई (समुद्र में तेल रिसाव) के कारण समुद्री जीव-जंतुओं और पक्षियों को हानि होती है तथा मैंग्रोव वनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिनमें तेल फंस जाता है और फूल खिलने, फल बनने तथा अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है।
- इससे प्रभावित मछलियों और समुद्री खाद्य वस्तुओं की गंध अप्रिय हो जाती है अतः तेल रिवाव के कारण मछलियों की उत्पादन सुविधाओं को होने वाली आर्थिक क्षति से समुद्री खाद्य उद्योग को काफी खतरे का सामना करना पड़ता है।
- समुद्री तल पर फेंका गया ड्रिल का कचरा ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है और इससे निचले तलछटों पर विषैले सल्फाइड बनते हैं जिससे समुद्र तल पर रहने वाले जीव मर जाते हैं।
- महासागरों में प्रदूषण से, इनसे प्राप्त होने वाली सुविधायें (यथा-औषधि पौधे एवं जीव, खाद्य पदार्थ, तटीय पर्यटन तथा अन्य समुद्री पौधे एवं जीव आदि) दूषित हो जाती हैं, जिससे मानव को काफी सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

तेल रिसाव से निपटने के कुछ उपाय

- तेल का विखंडन करने या हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों अथवा जैविक कारकों का उपयोग किया जाता है, इसे जैविक उपचार विधि कहते हैं। विशिष्ट जीवाणु पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
- नियंत्रित दहन प्रणाली के द्वारा पानी में फैले हुए तेल की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
- निर्वात विधि के द्वारा समुद्र तटों और पानी की सतह से तेल को हटाया जाता है। बूम, समुद्री सतह पर तैरते हुए बड़े अवरोध होते हैं जो तेल को एकत्र कर उसे जल से ऊपर उठाते हैं।
- स्किमर्स के द्वारा भी समुद्री सतह से तेल को हटाया जाता है। स्किमर्स तेल की सतह से फेन हटाते हैं। सॉर्बेंट्स,बड़े अवशोषक होते हैं, जो तेल का अवशोषण करते हैं।

तेल रिसाव से संबन्धित कानून

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल रिसाव से हुई क्षति के लिये पर्याप्त, शीघ्र तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी ऑफ बेकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज, 2001' है जिसके मुताबिक तेल रिसाव से हुए नुकसान के लिये जहाजों के मालिक जिम्मेदार होते हैं। इस संधि का भारत ने भी अनुसमर्थन किया है।
- भारत के अन्दर तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों को तेल रिसाव से होने वाली क्षति से रक्षा करने हेतु 1980 से तेल रिसाव प्रबंधन कार्यक्रम बना था।
- भारत में तेल रिसाव आपदा के मामले में संकट प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है तथा तेल रिसाव होने की स्थिति में भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए तटरक्षक बल समन्वयकारी एजेंसी है।

8. कोविड- 19 का डेल्टा वैरिएंट

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि भारत में पाए गए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट B.1.617 का केवल एक स्ट्रेन B.1.617.2 ही अब 'चिंता का सबब' है। डबल्यूएचओ ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के बाकी के दो स्वरूप में संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। B.1.617 स्वरूप सबसे पहले भारत में पाया गया और ये तीन स्वरूप बी.1.617.1, बी.1.617.2 और बी.1.617.3 में विभाजित हैं।

कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट

- भारत में पहली बार कोरोना के जिस प्रकार का पता चला था वो बी.1.167.2 था। ये भारत में सबसे पहले पाए गए तीन में से एक उप-प्रकार है। ये भारत में अक्टूबर 2020 में पाया गया था।
- भारत में पहली बार मिले बी.1.167.2 वैरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने न केवल 'डेल्टा वैरिएंट' नाम दिया है बल्कि इसे बतौर 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' (variant of concern) वर्गीकृत भी किया है। ये स्ट्रेन अब तक दुनिया के करीब 60 देशों में मिल चुका है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी भी वैरिएंट को चिंताजनक तब माना जाता है जब उसमें संक्रमण की क्षमता अधिक दिखती है या फिर मूल स्वरूप में कोई अन्य बदलाव दिखते हैं। किसी भी वैरिएंट को चिंताजनक घोषित करने के पहले इवोल्यूशन वर्किंग ग्रुप से सलाह ली जाती है।
- WHO के मुताबिक, B.1.617.2 वेरिएंट अभी भी एक VOC रहने वाला है। इसके अलावा, कोरोनावायरस के तीन अन्य वेरिएंट भी इस कैटेगरी में रहने वाले हैं। इसके पीछे की वजह इन वेरिएंट्स का वायरस के ऑरिजनल वर्जन से अधिक खतरनाक होना है। साथ ही इन वेरिएंट्स का तेजी से फैलना और कुछ वैक्सीन पर अप्रभावी होना भी एक वजह है।

सभी वेरिएंट्स को दिए गए नए नाम

- विदित हो कि WHO ने कोविड -19 वेरिएंट B.1.617.2 को नया नाम दिया। इसे अब वेरिएंट डेल्टा (Delta) के नाम से जाना

जाएगा। इसके साथ ही सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिले वायरस के B.1.1.7 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया।

- वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले B.1.351 को बीटा नाम मिला है और नवंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए P-1 वेरिएंट को अब गामा नाम दिया गया। गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में कोरोना के वेरिएंट B.1.617.2 को 'भारतीय वेरिएंट' कहे जाने पर ऐतराज जताया था।

म्यूटेशन

- म्यूटेट होने का मतलब है वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। उत्परिवर्तन (Mutation) का आशय एक जीवित जीव या किसी वायरस की कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ (जीनोम) में परिवर्तन से है जो अधिकांशतः स्थायी होता है तथा कोशिका या वायरस के वंशजों में प्रसारित/संचारित होता है।
- दरअसल, हर वेरियंट की पहचान उनके जेनेटिक मटीरियल में बदलाव या म्यूटेशन से होती है। sars cov-2 एक ऐसा RNA वायरस है जो एमिनो एसिड के करीब 30 हजार क्षार युग्मोन से बना है, इन क्षार युग्मों से किसी में भी बदलाव म्यूटेशन की वजह बंता है, जिससे वायरस का आकार और व्यवहार बदल जाता है।
- डेल्टा वेरिएंट' के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन हैं, जो काफी संक्रामक हैं। डबल म्यूटेंट वायरस के स्पाइक प्रोटीन (Spike Protein) वाले क्षेत्रों में जोखिम को बढ़ा सकता है।

वेरिएंट ऑफ कंसर्न

- वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऐसे वेरिएंट होते हैं जो संक्रामकता में वृद्धि करने के साथ पिछले सारे वैरिएंट्स से कई गुना ज्यादा संक्रामक होते हैं।

9. अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

चर्चा का कारण

- भारतीय रेलवे के अनुसंधान में मुख्य भूमिका निभाने वाला अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन (आरडीएसओ) 'एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड्स (बीआईएस) का पहला मानक विकास संगठन (एसडीओ) संस्थान बन गया है।

प्रमुख बिन्दु

- एक राष्ट्र एक मानक की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसी संस्थान को एसडीओ की मान्यता दी जाती है।
- इससे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत किया जा सकेगा। आरडीएसओ भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का एकमात्र संस्थान है।
- इसका उद्देश्य भारत में रेल परिवहन क्षेत्र के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए मानक का विकास करना है। इसकी मान्यता तीन साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

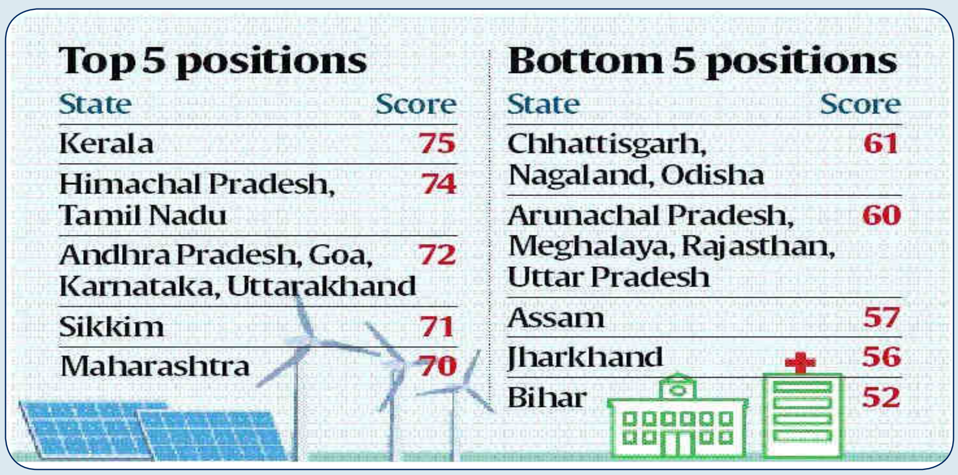

Top 5 positions	
State	Score
Kerala	75
Himachal Pradesh, Tamil Nadu	74
Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand	72
Sikkim	71
Maharashtra	70

Bottom 5 positions	
State	Score
Chhattisgarh, Nagaland, Odisha	61
Arunachal Pradesh, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh	60
Assam	57
Jharkhand	56
Bihar	52

राष्ट्रीय मानक निकाय योजना

(National Standards Body Scheme)

- BIS ने इस योजना को मौजूदा क्षमताओं और समर्पित डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता को समेकित और एकीकृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है जो विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास में लगे भारत के विभिन्न संगठनों के पास उपलब्ध हैं।

RDSO

- लखनऊ में आरडीएसओ, रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान और डिजाइन विंग है। यह भारत का अग्रणी मानक तैयार करने वाला निकाय है जो रेलवे क्षेत्र के लिए मानकीकरण कार्य करता है।

SDO मान्यता का अर्थ है

- SDO (Standard Developing Organization) की मान्यता के साथ, RDSO (Research Design - Standards Organization) की मानक निर्माण प्रक्रियाएं आम सहमति आधारित निर्णय लेने पर अधिक केंद्रित हो जाएंगी।
- यह प्रारंभिक चरणों से मानक बनाने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों जैसे उद्योग, शिक्षा, परीक्षण गृहों, उपयोगकर्ताओं, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं आदि को व्यापक रूप से संलग्न करेगा।
- इस टैग के साथ, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी और गुणवत्ता में सुधार होगा। यह आयात निर्भरता को भी कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

सर अनिरुद्ध जगन्नाथ

लक्ष्मीनंदन बोरा

डेविड डियोप

प्रदीप चंद्रन नायर

एंतोनियो गुतेरस

छत्रपति शिवाजी महाराज

अनूप चंद्र पांडेय

1. सर अनिरुद्ध जगन्नाथ

- मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। दो बार मॉरीशस के राष्ट्रपति और छह बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले जगन्नाथ को 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

राजनीतिक सफर

- जगन्नाथ ने 2003 से 2012 तक मॉरीशस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1982 से 2017 तक छह बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। बाद में उन्होंने अपने बेटे प्रविंद जगन्नाथ के लिए अपना पद छोड़ दिया। अनिरुद्ध जगन्नाथ पेशे से वकील थे और उन्होंने 1963 में विधान परिषद के चुनाव के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
- 1951 में वह ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय के लिंकन इन में कानून का अध्ययन करने गए। 1965 में, उन्होंने देश की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लंदन में संवैधानिक सम्मेलन में भाग लिया। जगन्नाथ चागोस द्वीपसमूह के वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और चागोसियन समुदाय की भलाई को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष में अग्रणी थे। उनके संघर्ष के चलते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

(आईसीजे) ने निर्णय दिया कि चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस गणराज्य के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है।

2. लक्ष्मीनंदन बोरा

- असम के जानेमाने साहित्यकार लक्ष्मीनंदन बोरा का हाल ही में निधन हो गया। कोविड के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते वे गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे।

परिचय

- लक्ष्मीनंदन बोरा असमिया भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। भारत के असम राज्य में स्थित नौगाँव जिले के कुजिदह गाँव में जन्में लक्ष्मीनंदन बोरा जोरहाट के असम कृषि विश्वविद्यालय में कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष थे। उनकी कृति 'पाताल भैरवी' को 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। उन्हें बिरला फाउंडेशन द्वारा 2008 के सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 2002 में प्रकाशित उपन्यास 'कायाकल्प' के लिए दिया गया। वे अब तक 56 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिसमें उपन्यास, कहानी संग्रह, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और जीवनी शामिल है। सरस्वती सम्मान

से अलंकृत होने वाले वे पहले असमिया साहित्यकार हैं।

3. डेविड डियोप

- डेविड डियोप (David Diop) अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास 'एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक' के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार (International Booker prize) जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। दो उपन्यासों के लेखक डीओप और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को साझा किया, जो अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखक और अनुवादक को जाता

मुख्य बिंदु

- "At Night All Blood is Black" एक उपन्यास है, जिसमे प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नदियाये (Alfa Ndiaye) पर आधारित है। यह पुस्तक 2018 में फ्रांसिसी भाषा में प्रकाशित हुई थी, बाद में 2020 में यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुई।

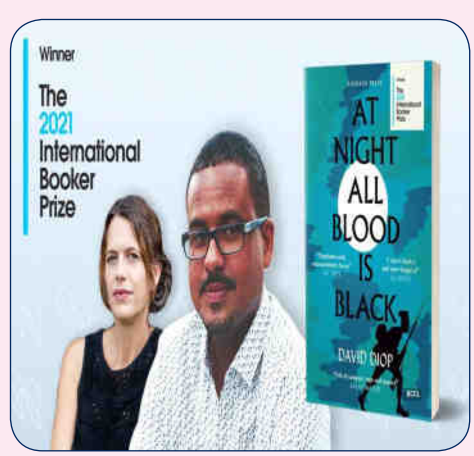

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
(International Booker Prize)

- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार वर्ष 2005 में दिया गया था, यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुदित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को वर्ष 2019 तक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।

4. प्रदीप चंद्रन नायर

- लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल्स (उत्तर-पूर्व के प्रहरी के रूप में लोकप्रिय) के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें असम राइफल्स और उत्तर पूर्व का समृद्ध अनुभव है, उन्होंने पहले असम राइफल्स में एक इंस्पेक्टर जनरल और एक कंपनी कमांडर के रूप में कार्य किया है, इसके अलावा एक ब्रिगेड कमांडर के रूप में असम राइफल्स बटालियन की कमान संभाली है।

असम राइफल्स (Assam Rifles)

- असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्धसैनिक बल है। इसका गठन ब्रिटिश राज में वर्ष 1835 में किया गया था। पहले इसके नाम Cachar Levy हुआ करता था। 1917 में असम राइफल्स नाम रखा। इसका आदर्श वाक्य 'उत्तर-पूर्व के प्रहरी' (Sentinels of the North East) है। यह केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जबकि इसकी पैरेंट एजेंसी भारतीय सेना है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है।
- **नोटः** CISF, CRPF, BSF, ITBP तथा SSB केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इससे पहले इन बलों को अद्धसैनिक बल माना जाता था। परन्तु मार्च 2011 के बाद इन बलों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- भारत में "अद्धसैनिक बल" को किसी कानून के द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं

किया गया है। "अद्धसैनिक बल" का उपयोग असम राइफल्स (इसका प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि इसका संचालनात्मक नियंत्रण भारतीय थल सेना के पास है) तथा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) के लिए किया जाता है।

5. एंतोनियो गुतेरस

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतेरस के 18 जून को दोबारा इस विश्व निकाय के प्रमुख बनने का रास्ता साफ हो गया है। शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के लगातार दूसरी बार पांच साल के लिए महासचिव बनाने का प्रस्ताव निर्विरोध रूप से मंजूर हो गया है। उनका दूसरा कार्यकाल एक जनवरी, 2022 से शुरू होना है। भारत ने यह प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जाहिर की है। 15 देशों की सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को एक बैठक करके 193 सदस्यीय महासभा के लिए दूसरी बार गुतेरस को महासचिव बनाए जाने की सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है।
- एंटोनियो गुटेरेस ने एक जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव का कार्यभार संभाला था और उनका पहला कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अगले महासचिव का कार्यकाल एक जनवरी 2022 से शुरू होगा। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में जून 2005 से दिसंबर 2015 तक अपनी सेवाएं दी थीं। पुर्तगाल सरकार द्वारा नामित एंटोनियो गुटेरेस महासचिव पद के लिए एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार रहे हैं।

परिचय

- इनका जन्म पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 30 अप्रैल 1949 को हुआ था। प्रेस्टिजियस लिसड डे कैमोएस नाम के माध्यमिक विद्यालय में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। वर्ष 1971 में इन्होंने लिस्बन विश्वविद्यालय से

स्नातक उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रूप में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाली राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं। गुटेरेस 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन में भी दस साल तक कार्य किया।

6. छत्रपति शिवाजी महाराज

- भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक नायक हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की अस्मिता और गौरव के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। ऐसे ही नायकों में शिवाजी का नाम प्रमुख है जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के कारण इन्हें मराठा गौरव के नाम से भी पुकारा जाता है।

प्रारम्भिक जीवन

- शिवाजी का जन्म पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का काफी प्रभाव था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। छत्रपति शिवाजी की प्रारंभिक शिक्षा दादाजी कोंडदेव के निर्देशन में हुई।

मराठा साम्राज्य की स्थापना

- मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवाजी ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मराठी जनता को आपस में जोड़ने का काम किया एवं एक संगठित दल का निर्माण किया। बहुत जल्द उन्होंने पूना के निकट स्थित तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा शीघ्र ही शिवाजी ने 1646 ई. में ही बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ई. में बारामती, इन्द्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग जीता था। इन्होंने 1656 ई. में कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी जीत लिया। इस जीत के उपरांत 1656 ई. में ही शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई।
- छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 ई. में प्रतापगढ़ किले पर भी कब्जा किया था। हालांकि उसके बाद उन्हें मुगलों से पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उन्हें जीते हुए बहुत से इलाके मुगलों को लौटाने पड़े। शिवाजी महाराज के साथ सबसे हैरान करने वाली घटना तो 1966 में घटी, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। कुछ महीनों तक वह उनकी कैद में रहे, लेकिन एक दिन वह मुगल सैनिकों को चकमा देकर वहां से भाग निकले।

- शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से कैसे छूटे, इसके कई किस्से इतिहास में मौजूद हैं। कुछ किताबों के मुताबिक, जेल में जब मिठाई और फल बांटे जा रहे थे, तो वह उसी टोकरी में बैठ कर वहां से भाग निकले और रायगढ़ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कई अहम लड़ाईयां लड़ीं और कई किलों पर जीत हासिल की, जिसमें त्रिचूर, जिंजी, मैसूर आदि शामिल हैं। तीन अप्रैल, 1680 को उनका देहान्त हो गया। आज भी उन्हें दुनिया के महान राजाओं में गिना जाता है।

7. अनूप चंद्र पांडेय

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को चुनाव आयुक्त के पद परनियुक्त किया गया है। पांडेय आयोग में दो निर्वाचन आयुक्तों में से एक हैं। उनके अलावा राजीव कुमार भी निर्वाचन आयुक्त हैं तथा सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।
- वर्ष 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे पांडेय निर्वाचन आयोग में आने से पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण निगरानी समिति (उप्र) के सदस्य थे। उनके उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव रहने के दौरान प्रयागराज में कुंभ मेले और राज्य में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने वाले अनूप चंद्र 2019 अगस्त महीने तक पद पर रहे थे। वह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त भी रह चुके हैं। वह फरवरी, 2024 में 65 साल की आयु पूरा होने पर निर्वाचन आयोग की सेवा से मुक्त होंगे। अनूप चंद्र पांडेय 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर रहे। 29 अगस्त 2019 को वह यूपी के मुख्यर सचिव पद से रिटायर हुए थे। वहीं इन दिनों एनजीटी में यूपीनिगरानी समिति के मौजूदा सदस्य हैं।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित स्थान

नासिक में तीन नई गुफाओं की खोज

रायमोना राष्ट्रीय उद्यान

थियानमेन चौक नरसंहार

हिमाचल प्रदेश द्वारा एंटी हेल गन परीक्षण

टुल्सा नस्लीय नरसंहार

तुर्की के समुद्र में Sea Snot

मोनाल पक्षियों की दो प्रजातियाँ

1. नासिक में तीन नई गुफाओं की खोज

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में त्रिरश्मी गुफा के समीप तीन और गुफाओं की खोज की है। ये गुफाएं किस काल की हैं इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यह संभवतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान रहे होंगे।

मुख्य तथ्य

- इन गुफाओं को वर्तमान परिसर की विपरीत दिशा में खोजा गया था। वे मौजूदा परिसर से लगभग 70-80 फीट ऊपर हैं और एक खड़ी पहाड़ी से उकेरी गयी हैं। वे भिक्षुओं के आवासों की तरह दिखती हैं और वर्तमान परिसर से पुरानी हैं। इन सभी गुफाओं में बरामदे और भिक्षुओं के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर का मंच शामिल है। भिक्षुओं के ध्यान करने के लिए उनके पास विशेष व्यवस्था है। गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र और इंडो-यूनानी वास्तुकला के डिजाइन वाली मूर्तियां भी हैं।

पांडवलेनी गुफाएं (Pandavleni Caves)

- पांडवलेनी गुफाओं को पहले 'त्रिरश्मी गुफा' (Trirashmi Caves) कहा जाता था। ये गुफाएं 25 गुफाओं का एक समूह है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच त्रि-रश्मी पहाड़ी से उकेरी गई हैं। इन 25 गुफाओं में विहार और चौत्य प्रमुख गुफाएं हैं। गुफा का परिसर 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन (Captain James Delamaine) द्वारा खोजा गया था। यह एक ASI संरक्षित स्थल और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।

2. रायमोना राष्ट्रीय उद्यान

- हाल ही में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान (Raimona National Park) को असम का छठवाँ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है।

रायमोना राष्ट्रीय उद्यान

- रायमोना राष्ट्रीय उद्यान (Raimona National Park), भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) के तहत कोकराझार जिले में आता है।
- असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान लगभग 422 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान असम के सन्निहित वनों का हिसा है। यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, सुनहरे लंगूर, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण और हॉर्नबिल आदि वन्यजीव पाये जाते हैं।

असम के अन्य पाँच राष्ट्रीय उद्यान

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
2. मानस राष्ट्रीय उद्यान,
3. नामेरी राष्ट्रीय उद्यान,
4. ओरंग राष्ट्रीय उद्यान,
5. डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान।

राष्ट्रीय उद्यान

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक, नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक, पशु-पक्षी, वनस्पति, भू-आकृति, जैव संरचना के महत्व, संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है।
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम -1972, राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है।
- पर्याप्त पारिस्थितिकी, जिओमोर्फिकल तथा प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है।
- केंद्र सरकार भी कतिपय परिस्थितियों में नेशनल पार्क घोषित कर सकती है।
- भारत में नेशनल पार्क, आईयूसीएन (IUCN) के अंतर्गत श्रेणी II में सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र हैं।
- भारत में पहला नेशनल पार्क वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है।

3. थियानमेन चौक नरसंहार

- 4 जून को चीन में थियानमेन नरसंहार की 26वीं बरसी मनाई गई। 4 जून 1989 को थियानमेन स्क्वायर पर जमा हुए लोकतंत्र समर्थकों पर चीन सरकार ने सैन्य कार्रवाई कर खदेड़ा था। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उस समय चीन की इस कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना की गई थी। तब से लेकर आज तक चीनी सरकार बेहद सर्तकता बरतती है। वह थियानमेन स्क्वायर में पर्यटकों को आने तो देती है, लेकिन उसने इस स्थल को नरसंहार से जुड़ी किसी भी मेमोरियल में तब्दील नहीं होने दिया है।
- 4 जून 1989 को डेंग झियांगपिंग और दूसरे नेताओं ने सेना को थियानमेन चौक खाली करवाने का आदेश दिया। हालांकि पार्टी यह दावा करती है कि चौक पर कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, लेकिन उसके आस-पास की सड़कों पर सेना की गोलियों का शिकार होकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए थे। 10 हजार से ज्यादा गिरफ्तार किए गए थे।

प्रदर्शनकारीयों की मुख्य 7 मांगे थी

1. ह्यू याओबंग के लोकतंत्र के मॉडल को अपनाया जाए।
2. बुर्जुआ लिबरल होना।
3. नेताओं की संपत्ति को सार्वजनिक करना।
4. प्रेस संेसरशिप हटाना।
5. शिक्षा के लिए फण्ड।
6. छात्रों पर लगे सारे रोक हटाये जाए।
7. हमारे सभी ओबेजक्टिव को पूरे देश मे कवरेज दी जाए।

कम्युनिस्टों द्वारा किए गए नरसंहार का इतिहास

- चीन में कम्युनिस्ट सरकार 1949 से अस्तित्व में हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत नरसंहारों से हुई थी। 1948-1951 यानि तीन सालों में 10,00,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गयी थी। यह सिलसिला कभी नहीं थमा। साल 1967 में 5000 लोगों को मार दिया गया. ऐसे ही 1979, 1994, 1998 और हाल ही में 2014 में भी नरसंहार हुए है।

4. हिमाचल प्रदेश एंटी हेल गन परीक्षण

- ओलावृष्टि के कारण फसल को खराब होने से बचाने के लिए वाले बागवानों की सहायता हेतु, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 'ओलावृष्टि रोधी बंदूक' अर्थात 'एंटी-हेल गन' (Anti-Hail Guns) के उपयोग का परीक्षण किया जाएगा।

'एंटी-हेल गन'

- एंटी-हेल गन (Anti-Hail Gun), बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए 'आघात तरंगें' अर्थात शॉक वेव्स (Shock Waves) उत्पन्न करने वाली एक मशीन है।
- यह एक उल्टे टावर से मिलता-जुलता कई मीटर ऊँचा एक स्थिर ढांचा होता है और इसमें आकाश की ओर खुलने वाली एक लंबी और संकीर्ण शंक्वाकार नली लगी होती है।
- बंदूक के निचले हिस्से में एसिटिलीन गैस और हवा का विस्फोटक मिश्रण भरकर, इसे

दागा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 'शॉक वेव्स' निकलती हैं। इन 'शॉक वेव्स' की गति सुपरसोनिक विमान से निकलने वाली तरंगों की भांति ध्वनि की गति से तेज होती है।
- ये शॉक वेव्स बादलों में जल-बूंदों को ओलों में बदलने से रोक देगी, जिससे कि ये साधारण बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरेंगी।
- ओलों (Hails) का निर्माण 'कपासी वर्षा मेघों' (Cumulonimbus Clouds) द्वारा होता है, जो काले विस्तृत बादल होतें हैं एवं विद्युत गर्जन का कारण बनते है। इन बादलों में उपस्थित हवा जल की बूँदों को उनके बर्फ के रूप में जमने तथा भारी होकर ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर गिरने तक ऊपर धकेलती रहती है।

5. टुल्सा नस्लीय नरसंहार

- हाल ही में अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट में टुल्सा नामक स्थान पर हुए टुल्सा नस्लीय नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति बाइडेन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और उसके तीन सर्वाइवर्स से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में उस स्थान पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हैं, जहां सैकड़ों ब्लैक अमेरिकियों को व्हाइट मॉब ने 100 साल पहले मौत के घाट उतार दिया था।

परिचय

- यह सब उस अफवाह के साथ शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि डिक रोलैंड नामक एक काले युवा ने डाउनटाउन टुल्सा होटल में एक गोरी लड़की पर हमला कर दिया है। यह घटना 30 मई 1921 की है। उस दिन डिक रोलैंड की मुलाकात सारा पेज नामक महिला से एक एलीवेटर पर हुई थी। इसके बाद क्या हुआ इसका ब्योरा हर शख्स के हिसाब से अलग-अलग है। इस घटना के बारे में खबरें गोरे समुदाय के बीच पहुंचने लगीं। ये सूचनाएं बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही थीं। टुल्सा पुलिस ने रोलैंड को अगले दिन अरेस्ट कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी।
- 31 मई को टुल्सा ट्रिब्यून न्यूजपेपर में छपी एक भड़काऊ खबर में कालों और गोरों को अदालत के पास आपस में झड़प के लिए उकसाया गया था। यहां पर शेरिफ और उनके लोगों ने टॉप फ्लोर को बंद कर दिया था ताकि रोलैंड को संभावित लिंचिंग से बचाया जा सके। इस दौरान गोलियां चलीं और अल्पसंख्यक अफ्रीकी अमेरिकी ग्रीनवुड जिले की ओर विस्थापित होने लगे। यह जगह ब्लैक वॉल स्ट्रीट के तौर पर जानी जाती है जो कि कारोबारी और आर्थिक समृद्धि के लिए मशहूर थी।
- एक जून की सुबह गोरे दंगाइयों ने ग्रीनवुड को लूटा और जलाया। इसके बाद ओक्लाहामा के तत्कालीन गवर्नर जेम्स रॉबर्ट्सन ने मार्शल लॉ का एलान कर दिया। दंगों के दौरान 35 ब्लॉक खाक कर दिए गए। इसका मतलब है कि 1,200 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया गया था। शुरुआत में कहा गया था कि 39 लोग मारे गए हैं, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि कम से कम 300 लोग मारे गए थे।

6,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय के लोग थे।

ब्लैक वॉल स्ट्रीट

- 1900 के दशक की शुरुआत में ग्रीनवुड जिला एक उभरता हुआ शहर था। यहां मूवी थियेटर, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और फोटोग्राफी स्टूडियो थे। ब्लैक वॉल स्ट्रीट नाम इसके आर्थिक उभार को दिखाता है। यह देश में काले समुदाय के लिए सबसे बेहतर शहर माना गया था। लेकिन दंगों, आगजनी और हिंसा ने इस शहर को बर्बाद कर दिया था।

6. तुर्की के समुद्र में Sea Snot

- हाल ही में तुर्की के सी ऑफ मारमारा को समुद्री गोंद या 'Sea Snot' ने ढंक लिया है और इससे बड़ी तादाद में समुद्री जीवों के मरने की आशंका जताई जाने लगी है। जेली के जैसा यह पदार्थ उस समय पैदा होता है जब शैवाल जलवायु परिवर्तन और जल प्रदूषण की वजह से पोषक तत्वों से भर जाता है। समुद्र के अंदर जेली के फैलने पर पर्यावरणविदों और बॉयोलॉजिस्टों ने चेतावनी दी है।

क्या है समुद्र में फैलती ये जेली?

- सी-स्नॉट समुद्र में बनने वाला एक लसलसा पदार्थ है। ये तब बनता है जब शैवाल बहुत ज्यादा पोषण पाकर तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये कोई बढ़िया स्थिति नहीं, बल्कि शैवालों का बढ़ना समुद्र के लिए काफी खतरनाक है। यहां ये भी जान लें कि समुद्र या कहीं पर भी शैवाल का बढ़ना जल-प्रदूषण का नतीजा है। खुद पर्यावरण के जानकार भी ये मान रहे हैं कि शैवालों का बढ़ना और समुद्र में आई लसलसाहट क्लाइमेंट चेंज और फैक्ट्रियों-घरों की गंदगी पानी में मिलने का नतीजा है।

पहले भी आ चुकी है समस्या

- साल 2007 में भी सी-स्नॉट दिखा था लेकिन इस बार ये ज्यादा बुरी तरह से फैला हुआ है। देश के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी पर्यावरण आपदा मानी जा रही है। समुद्र के ऊपर मोटी परत जम जाने से नीचे मछलियों और वनस्पतियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण भारी संख्या में मछलियों समेत कोरल और स्पंज जैसी वनस्पतियां खत्म हो चुकी हैं।

मारमरा समुद्र

- तुर्की का मारमरा समुद्र (Sea of Marmara), काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता

है। ये वहां के लोगों के लिए लाइफलाइन भी कहलाता है। इसकी सीमा पर तुर्की के पांच राज्या हैं, साथ ही देश की व्यापारिक राजधानी इस्तांबुल भी यहीं है। ऐसे में जाहिर है कि मारमरा समुद्र से काफी सारी व्यापारिक गतिविधियां होती रहीं। लेकिन अब समुद्र में जेली जैसी चिपचिपा सी-स्नॉट जमा हो गया है, जिससे जहाज या नावों का गुजरना असंभव हो गया है और देश के भीतर व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है।

7. मोनाल पक्षियों की दो प्रजातियाँ

- हाल ही में, वन्यजीव उत्साही लोगों की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में समुद्र तल से 4,173 मीटर ऊपर माउंट एको डंबिंग (Mount Eko Dumbing) पर मोनाल पक्षियों की दो प्रजातियों को देखा है। खोजी गयी प्रजाति मोनाल और स्क्लेटर मोनाल ध्यातव्य है कि हिमालयी मोनाल (Lophophorus impejanus) अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है जबकि स्क्लेटर मोनाल (Lophophorus sclateri) चीन और म्यांमार में पाया जाता है।

मोनाल पक्षी (Monal)

- मोनाल पक्षी तीतर (pheasant) परिवार के जीनस लोफोफोरस से संबंधित है जिसे फासियानिडे (Phasianidae) कहा जाता है। नर पक्षियों में रंगीन, इंद्रधनुषी पंख होते हैं। वे आहार के रूप में जड़ों, बल्बों और कीड़ों को पसंद करते हैं। आवास विनाश और शिकार के कारण उन्हें कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सियांग जिला (Siang District)

- यह अरुणाचल प्रदेश का 21वां जिला है जिसे पश्चिम सियांग और पूर्वी सियांग जिलों को विभाजित करके बनाया गया था। इसका उद्घाटन 27 नवंबर, 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी द्वारा किया गया था। इसका नाम सियांग नदी पर रखा गया है जो इस जिले से होकर बहती है। माना जाता है कि सियांग की उत्पत्ति हिमालय के उत्तरी हिस्से में अंगसी ग्लेशियर (Angsi Glacier) से हुई है। इस जिले में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति (Adi Tribe) निवास करती है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विश्व रक्तदान दिवस

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

विश्व प्रत्यायन दिवस

विश्व ट्यूमर दिवस

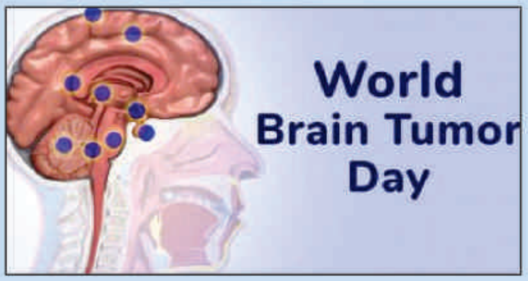

विश्व महासागर दिवस

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस

1. विश्व रक्तदान दिवस

- 14 जून को दुनियाभर में विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है।

विश्व रक्तदान दिवस 2021 थीम और स्लोगन

1. **2021 का थीम:** Celebrating the Gift of Blood
2. **2021 का स्लोगन:** Share Life, Give Blood

विश्व रक्त दाता दिवस का इतिहास

- हर साल 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस मनाया जाता है, इसे 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है।
- वर्ष 2004 में "विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ तथा रेड क्रिसेंट समाज" के द्वारा 14 जून को वार्षिक तौर पर मनाने के लिये पहली बार इसकी शुरुआत हुयी। इसका मुख्य कारण था कि रक्त जैसी जरुरी चीज के लिए लोगों को पैसा खर्च न करना पड़े और आसानी से मुश्किल परिस्थिति में रक्त उपलब्ध हो सके।
- रक्तदाता इस दिन एक मुख्य भूमिका में होता है क्योंकि वो जरुरतमंद व्यक्ति को जीवन बचाने वाला रक्त दान करते हैं। साथ ही यह भी सदस्यों का उद्देश्य था कि दुनिया भर में सभी देश प्रेरित हो, और पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, स्वैच्छिक, सुरक्षित और अवैतनिक रक्त दान को बढ़ावा मिले।

विश्व रक्तदान दिवस का क्या महत्व है?

- रक्त की आवश्यकता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह उससे आगे जाता है। दुनिया भर में रक्तदान की जरूरत है, चाहे वह सामान्य परिस्थितियां हों या आपात स्थिति। विश्व रक्तदाता दिवस लोगों को यह शिक्षित करने के लिए है कि सुरक्षित रक्त कितना महत्वपूर्ण है और यह उन लोगों के जीवन में क्या कर सकता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता फैलाना है जो हर कोई अपना योगदान दे सकता है और यह पर्याप्त से अधिक होगा।

2. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

- हर साल विश्व भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है।

बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का इतिहास

- इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के अनुसार, विश्व भर में 5 से 17 साल की उम्र तक के कई बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं जो उन्हें सामान्य बचपन से वंचित करते हैं, जैसे कि पर्याप्त शिक्षा, उचित स्वास्थ्य देखभाल, अवकाश का समय या बस बुनियादी स्वतंत्रता। 2002 में, संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो काम की दुनिया को नियंत्रित करती है, ILO ने इसी वजह से वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का महत्व

- यह दिन मुख्य रूप से बच्चों के विकास पर केंद्रित है और यह बच्चों के लिए शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रचारित 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए कई संगठन, आईएलओ इत्यादि प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए।

भारत में बाल श्रमिक

- राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, 5-14 वर्ष के बच्चो की भारत में जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इनमें से कुल बाल आबादी 260 मिलियन का लगभग 10 मिलियन (लगभग 4%) बाल श्रमिक हैं जो मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। 15-18 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं।

3. विश्व प्रत्यायन दिवस

- विश्व प्रत्यायन दिवस (World Accreditation Day) 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच (International Accreditation Forum) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (International Laboratory Accreditation Cooperation) द्वारा शुरू की गई थी।

भारत

- भारत में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (Quality Council of India) द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा, National Accreditation Board for Testing and calibration Laboratories और National Accreditation Board for Certification Bodies द्वारा वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।
- FSSAI के अनुसार, भारत में प्रत्यायन के संबंध में वर्तमान आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
  - प्रवीणता परीक्षण
  - रैपिड टेस्ट किट विकसित करना
  - मान्यता प्राप्त संदर्भ सामग्री उत्पादकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए
  - सूचना के आदान-प्रदान के लिए एकीकृत प्रणाली
  - खाद्य विश्लेषण के लिए रैपिड टेस्ट किट
  - उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यायन योजना
  - भारत को भी वर्चुअल असेसमेंट को संस्थागत बनाने की जरूरत है।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (Quality Council of India)

- भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में हुई थी। QCI का मुख्य उद्देश्य देश में सभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना है। इसे नीदरलैंड मॉडल के आधार पर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में स्थापित किया गया था। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा स्थापित की गयी थी। QCI के प्रमुख प्रवर्तक CII (भारतीय उद्योग परिसंघ), FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) हैं।

4. विश्व ट्यूमर दिवस

- विश्व ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था।
- दुनिया भर में हर दिन 500 से अधिक नए मामलों में ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है। ब्रेन मेटास्टेस का कारण बनने वाले ट्यूमर वाले रोगियों की संख्या इससे भी अधिक है। यह बच्चों में सबसे आम प्रकार का कैंसर माना जाता है।

ब्रेन ट्यूमर क्या है?

- ब्रेन ट्यूमर एक विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं। ये ट्यूमर या तो कैंसर युक्त हो सकते हैं या यह गैर-कैंसर युक्त यह आपके मस्तिष्क के किसी भी हिस्से जैसे झिल्लियों, कपाल नसों, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि में उत्पन्न हो सकता है।
- वैसे तो ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी जरूरी होती है। इसके लिए कई ऐसी टेक्निक डेवलप हो चुकी हैं जिससे इलाज काफी आसान हो चुका है। 20 से 40 उम्र के लोगों को ज्यादातर नॉन कैंसर और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कैंसर वाले ट्यूमर होने की संभावना बनी रहती है। नॉन कैंसरस ट्यूमर के बढ़ने की स्पीड, कैंसर वाले ट्यूमर की तुलना में धीमी होती है।

5. विश्व महासागर दिवस

- प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस (World Ocean Day) मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है।
- महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण के वजह से महासागर धीरे-धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

इस साल की थीम

- इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल की विश्व महासागर दिवस की थीम 'द ओशन: लाइफ एंड लाइवलीहुड' रखी गई है। इसका उद्देश्य लोगों में ये जागरूकता पैदा करना कि ये महासागर ही हैं जो पूरी दुनिया में प्रोटीन उपलब्ध कराने का सबसे बड़ी जरिया है।

पृष्ठभूमि

- विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के दौरान सुझाया गया था। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर, 2008 को इस दिन को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया।

महत्व

- महासागर लोगों के दैनिक जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह जीवमंडल (biosphere) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें पानी प्रदान करता है जो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि, महासागर वर्षों से मानव निर्मित

विनाश का खामियाजा भुगत रहे हैं। समुद्र में औद्योगिक कचरा और अवांछित कचरा उसके प्राकृतिक संसाधनों से खराब और अस्थिर कर रहा है। इस प्रकार, महासागरों को बचाना महत्वपूर्ण हो जाता है और विश्व महासागर दिवस इसके लिए प्रतिबद्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Marine Organization)

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन 1973 में तेल द्वारा जहाजों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था।

6. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

- हाल ही में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस-2021 (World Food Safety Day-2021) मनाया गया है। इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम ' स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन' है।

प्रमुख बिन्दु

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस-2021 के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भी कई कार्यक्रमों का वर्चुअल रूप से आयोजन किया है।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के मुताबिक यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आधारित पोषण नीतियों और पोषण शिक्षा का एक अनिवार्य घटक बने। भारत सरकार का लक्ष्य ऐसे कदम को प्रात्साहित करना है जो खाद्य जनित जोखिम को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने में सहायता करे।
- उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा किसी देश की ठोस और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्धारकों में से एक है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

- प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। 7 जून, 2019 को प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था।
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार तक पहुंच, पर्यटन और सतत विकास के प्रबंधन आदि हेतु खाद्य जोखिमो के प्रति लोगो का ध्यान आकर्षित किया जा सके।
- इसके अलावा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का लक्ष्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने

और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करने हेतु जागरूकता पैदा करना है।

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) नोडल एजेंसी है जो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत है।
- यह दिन विश्व भर में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है कि खाद्य केवल एक कृषि संबंधी और व्यापार वस्तु नहीं है बल्कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा भी है।

7. विश्व पर्यावरण दिवस

- हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस - 2021 मनाया गया है।

प्रमुख बिन्दु

- विश्व पर्यावरण दिवस-2021 दुनिया भर में "पारितंत्र/ प्रकृति संरक्षण" की थीम के साथ मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर महाद्वीप और हर महासागर में प्रकृति/ पारितंत्र के पतन को रोकना और इस प्रक्रिया को उत्क्रमित करना है।
- इस थीम में योगदान देते हुए भारत सरकार का फिल्म प्रभाग, 5 से लेकर 6 जून 2021 तक 'प्रकृति के संग : पर्यावरण पर फिल्मोत्सव' की ई-स्क्रीनिंग के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने कई वर्षों से पर्यावरण के पुनरूत्थान तथा संरक्षण के लिए प्रभावी संदेश के साथ जागरूकता पैदा करने वाली वृत्तचित्रों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विश्व पर्यावरण दिवस

- 5 जून को मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंधों को दर्शाते हुए पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
- वैश्विक समुदाय के द्वारा पहली बार 5 जून, 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु की थी।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक: रुझान-2021

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक; रुझान, 2021 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक बेरोजगारी 2022 में 205 मिलियन होने की उम्मीद है, जो 2019 के 187 मिलियन के मुकाबले काफी ज्यादा है।

2. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- कोरोना महामारी के कारण विश्व भर में 100 मिलियन से अधिक श्रमिक गरीबी के दुष्चक्र में चले गए हैं। नोवल कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से प्रेरित नौकरियों की कमी 2021 में 75 मिलियन थी जो 2022 में 23 मिलियन होने की उम्मीद है।
- COVID-19 महामारी के कारण दुनिया भर में श्रम बाजारों में अभूतपूर्व व्यवधान आया है, जिसने युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित किया है और उनकी शिक्षा में व्यवधान लाया है, खासकर दुनिया के उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल बुनियादी ढांचा कम विकसित है। साथ ही उनके लिए श्रम बाजार में प्रवेश करना और अपनी नौकरी पर बने रहना और भी कठिन बना दिया।
- महामारी ने लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को और बदतर बना दिया है, कई महिला श्रमिकों को श्रम बल से बाहर कर दिया है।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति वर्षों को जोखिम में डाल दिया और उन्हें अधिक पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में वापस धकेल दिया।
- अनौपचारिक और कम कुशल कामगारों के लिए घर से काम करना कोई विकल्प नहीं था।
- अक्सर सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच के बिना बहुतों को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए भारी स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ा।
- ILO की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित रूप से अतिरिक्त 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य अब गरीबी में जी रहे हैं।
- गरीबी दर में तेजी से हो रही वृद्धि काम के घंटे खोने के कारण है, क्योंकि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन लागू किया गया है और अधिकांश लोगों की नौकरी छूट गई है या फिर उनकी आय में कमी आ रही है।
- गरीबी के उन्मूलन की दिशा में बीते पाँच वर्षों में की गई समग्र प्रगति व्यर्थ हो गई है, क्योंकि गरीबी दर अब वर्ष 2015 के स्तर पर वापस आ गई है।
- वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में वैश्विक कामकाजी घंटों का 8.8 प्रतिशत का नुकसान हुआ, जो कि 255 मिलियन पूर्णकालिक रोजगार के समान है।
- वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर 6.3 प्रतिशत है, जो कि अगले वर्ष (2021-22) तक गिरकर 5.7 प्रतिशत हो जाएगी, किंतु तब भी यह पूर्व-महामारी (वर्ष 2019) दर यानी 5.4 प्रतिशत से अधिक है।
- महिलाओं के अवैतनिक कार्य के समय में वृद्धि हुई है और उन्हें अनुपातहीन रोजगार के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके अलावा महिलाओं पर बच्चों की देखभाल और होम स्कूलिंग गतिविधियों का भी असमान बोझ पड़ा है।
- नतीजतन पुरुषों के लिये 3.9 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिये रोजगार में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- अत: इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुमानित रोजगार वृद्धि दर महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं होगी।

3. आगे की राह

- कोविड-19 महामारी न केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, बल्कि यह एक रोजगार और मानव संकट भी है।
- यदि नौकरियों के सृजन में तेजी लाने, समाज के संवेदनशील वर्गों का समर्थन करने और आर्थिक रिकवरी को प्रोत्साहित करने के संबंध में मजबूत प्रयास नहीं किये जाते हैं तो मानव एवं आर्थिक क्षमता के नुकसान और उच्च गरीबी एवं असमानता के रूप में महामारी का प्रभाव वर्षों तक देखने को मिल सकता है।
- अत: उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने और सबसे संवेदनशील लोगों के लिये दीर्घकालिक श्रम बाजार की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु तत्काल प्रयास किया जाना आवश्यक है।

02 प्रोजेक्ट-75

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के लिए छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि यह मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने प्रोजेक्ट-75 इंडिया के अंतर्गत दी है।

2. क्या है प्रोजेक्ट-75-I

- प्रोजेक्ट 75-I के तहत सबमरीन का निर्माण करना है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। ये दोनों कंपनियां विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगी।
- समुद्री इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी हैं जो डीजल-इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। इनका साइज मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से पचास फीसदी तक बढ़ा होगा।
- इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से लैस छह पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- वर्ष 2007 में स्वीकृत प्रोजेक्ट 75 इंडिया, स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिये भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
- स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2017 में प्रख्यापित रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहली परियोजना होगी।
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल आयात पर निर्भरता कम करने के लिये घरेलू निर्माताओं को हाई-एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का उत्पादन करने के लिये प्रमुख विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की अनुमति देता है।
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत अधिग्रहण, रक्षा हेतु 'मेक इन इंडिया' में विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ निजी भारतीय फर्मों की भागीदारी को संदर्भित करता है।

3. आवश्यकता क्यों?

- दरअसल, चीन ने साल 2008 के बाद से ही एंटी-पाइरेसी पेट्रोल्स के लिए तीन जहाज छोड़ रखे हैं। यही कारण है कि अरब सागर से लेकर श्रीलंका से सटे समुद्र तक भारत ने अपनी नजरें टिका रखी हैं।
- भारतीय नेवी के पास करीब 140 सबमरीन और सरफेस वॉरशिप हैं, वहीं अगर पाकिस्तानी नेवी से तुलना करें तो उनके पास सिर्फ 20 ही हैं।
- यह परियोजना भारतीय उद्योग के लिए नई प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण क्षमताओं की उपलब्धता आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए देश को आगे बढ़ाएगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
- यह प्रौद्योगिकी के तीव्र गति से और अधिक महत्त्वपूर्ण अवशोषण की सुविधा प्रदान करने तथा भारत में पनडुब्बी निर्माण हेतु एक स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का काम करेगा।
- रणनीतिक दृष्टिकोण से यह आयात पर वर्तमान निर्भरता को कम करने में मदद करेगा और धीरे-धीरे अधिक आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति की निर्भरता सुनिश्चित करेगा।
- यह परिवर्तन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN, चीन) द्वारा परमाणु पनडुब्बी शस्त्रागार की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और हिंद-प्रशांत को भविष्य में विरोधी के वर्चस्व से बचाने के लिये किया गया है।

4. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में

- DAC रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिये नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेती है।
- DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार" पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन किया गया था।

03 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में वर्ष 2022 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Ranking 2022) जारी किया गया है। अग्रणी वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक 'क्यूएस (QS – Quacquarelli Symonds) द्वारा विश्व की अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18 वां संस्करण जारी किया गया है। इस बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 1300 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में भारत के 35 विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इनमें से एक संस्थान ऐसा है जिसे रिसर्च के मामले में दुनियाभर में पहला स्थान मिला है।

2. क्या है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings)?

- यह वार्षिक विश्वविद्यालय रैंकिंग Quacquarelli Symonds (QS) द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहले इसे Times Higher Education–QS World University Rankings के नाम से जाना जाता था। 2004 से 2009 तक, QS ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय लीग को प्रकाशित करने के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) पत्रिका के साथ सहयोग किया था। बाद में, दोनों ने रैंकिंग बनाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाये।
- क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) महत्त्वाकांक्षी पेशेवरों के लिये एक प्रमुख वैश्विक कॅरियर और शैक्षिक नेटवर्क है, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाना हैं। क्यूएस, संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिये तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करके उन्हें सफलतापूर्वक लागू करता है। इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का प्रकाशन वार्षिक स्तर पर होता है जिसमें वैश्विक रूप से समग्र सब्जेक्ट रैंकिंग शामिल हैं।
- निम्नलिखित छह संकेतकों के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है:
  - शैक्षणिक प्रतिष्ठा नियोक्ता की प्रतिष्ठा (Employer Reputation)
  - संकाय-छात्र अनुपात (Faculty&Student Ratio)
  - प्रकाशित शोध / संकाय (Citations per faculty)
  - अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात (Proportion of International Students)
  - अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात (Proportion of International Faculty)

3. रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- **वैश्विक संदर्भ में**
  - 'क्वाक्वेरेली साइमंड्स' (QS) एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग है जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेषज्ञ समूह' (IREG) का अनुमोदन प्राप्त है।
  - मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 10 वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है।
  - वर्ष 2006 के बाद पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया है।
  - स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल हुआ है।
  - सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तथा नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी तथा पेकिंग यूनिवर्सिटी, वैश्विक शीर्ष 20 विश्विद्यालयों में एकमात्र एशियाई विश्वविद्यालय हैं।
- **भारतीय संदर्भ में**
  - IIT गुवाहाटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (World University Ranking) में वैश्विक स्तर पर 395वां रैंक हासिल किया है।
  - क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसकी रैंकिंग 470 से बढ़कर इस संस्करण में 395वीं हो गई है, जो 'Citations per Faculty' श्रेणी में मजबूत सुधार के परिणामस्वरूप हुई है।
  - इस श्रेणी में, IIT गुवाहाटी ने 2021 में अपने स्कोर में 9 से सुधार करके 2022 में 94.8 का स्कोर हासिल किया है।
  - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, शीर्ष-200 रैंक में स्थान हासिल करने वाले भारत के तीन विश्वविद्यालय बने रहे।
  - जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार जगह हासिल की है, और इसे 561-570 बैंड में रखा गया है।
  - भारत के 35 विश्वविद्यालयों में से सत्रह ने CPF स्कोर में बढ़त हासिल की है, जबकि 12 विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन इस संकेतक में गिरा है।

4. चिंताएँ

- भारतीय विश्वविद्यालय क्यूएस के 'संस्थागत शिक्षण क्षमता' मापदंड में संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत के 35 विश्वविद्यालयों में से तेईस विश्वविद्यालयों की 'संकाय/छात्र अनुपात संकेतक' में गिरावट हुई है, और मात्र छह विश्वविद्यालयों ने इस संकेतक में सुधार किया है।
- संकाय/छात्र अनुपात' श्रेणी में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय 'शीर्ष 250' में शामिल नहीं है।
- रैंकिंग भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सटीक रूप से नहीं दर्शाती है, बल्कि यह काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय धारणा पर निर्भर है।
- स्कोर का आधा हिस्सा प्रतिष्ठा संकेतकों से आता है, जो किसी वस्तुनिष्ठ पद्धति के बजाय, धारणा पर आधारित होते हैं।
- यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस वर्ष स्कोर में सुधार केवल रैंकिंग एजेंसी द्वारा संख्याओं में हेरफेर के कारण हुआ है, जो वाणिज्यिक दबावों से प्रेरित है।

04 सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एसएजीई (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) कार्यक्रम और एसएजीई पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लांच किया है। एसएजीई पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला "वन-स्टॉप एक्सेस" होगा।

2. स्टार्ट-अप का चयन

- बुजुर्गों की मदद के लिए स्टार्ट-अप का चयन नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा. एसएजीई के तहत चुने गए स्टार्ट-अप वे होंगे जो स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए और इन्नोवेटिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे।
- एसएजीई कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए स्टार्ट-अप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (EEC) रिपोर्ट की सिफारिशों पर बनाई गई है।
- स्टार्ट-अप का चयन विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चयनित स्टार्ट-अप को एकमुश्त इक्विटी के रूप में 1 करोड़ रुपये तक का फंड दिया जाएगा।

3. एसएजेई कार्यक्रम

- एसएजेई कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे हितधारकों के लिए उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पहचान करना, मूल्यांकन करना, सत्यापित करना, एकत्र करना और वितरित करना है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन चयनित स्टार्ट-अप के माध्यम से बुजुर्गों को उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करेगा।
- अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस क्षेत्र में व्यापार के अवसर सामाजिक उद्यमों (गैर-लाभकारी, अनौपचारिक नेटवर्क), प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप (फिनटेक, एडुटेक, फूडटेक, हेल्थटेक, वेल्थटेक), कानूनी और वित्तीय सेवाओं (योजना समाधान, बीमा, मेडिको-लीगल), इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधित देखभाल प्रणाली (वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं, देखभाल केंद्र) जैसे क्षेत्रों में हैं।
- अनुसंधान और डेटा-संचालन कंपनियां और सोशल इंटरप्राइजेज इन्क्यूबेटरों को भी एसएजेई का हिस्सा बनने के लिए आगे आने की उम्मीद है।

4. इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों?

- भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2001 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5 प्रतिशत और 2050 तक 19.5 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।
- परिस्थिति को देखते हुए, भारत में विशेष रूप से कोविड के बाद के समय में एक अधिक मजबूत वरिष्ठ नागरिक देखभाल ईको सिस्टम बनाने की तत्काल आवश्यकता है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्ट-अप्स पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार बनाई गई है।

5. बुजुर्गों के लिये अन्य सरकारी पहलें

- **वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPOP):** वरिष्ठ नागरिकों के लिए (वृद्धावस्था गृह)/निरंतर देखभाल गृह, मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन और रख रखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना:** राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में देश के वृद्धजनों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत देश के वृद्ध नागरिको को केंद्र सरकार के द्वारा जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जायेगे। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरणों को शिविरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- **वय वंदना योजना:** बुजुर्गों पर विशेष ध्यान के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई PMVVY) 60 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8 फीसदी के गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था की गई है।
- **माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007:** माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) वृद्ध व्यक्तियों एवं माता-पिता के भरण-पोषण एवं देखरेख का एक प्रभावी व्यवस्था करती है।

05 विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, 2021: IEA

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) ने विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट (World Energy Investment Report) 2021 प्रकाशित की है।

2. प्रमुख बिन्दु

- **वैश्विक ऊर्जा निवेश में बढ़ोतरी:** इस साल वैश्विक ऊर्जा निवेश में फिर से उछाल आने और इसके सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
- **अक्षय ऊर्जा:** इस निवेश का अधिकांश हिस्सा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन उत्पादन से हटकर बिजली और अंतिम उपयोग क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होगा। नई बिजली उत्पादन क्षमता पर होने वाले कुल खर्च (+ 530 मिलियन) का लगभग 70% अक्षय ऊर्जा पर किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा जारी विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, भविष्य के ऊर्जा दृष्टिकोण के रूप में नवीकरणीय का पर्याप्त लाभ होगा क्योंकि यह तकनीकी विकास, अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति श्रृंखला और कार्बन-तटस्थ बिजली के लिए उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर है।
- **जीवाश्म ईंधन:** ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में भी निवेश में पर्याप्त वृद्धि (10 प्रतिशत) देखने को मिलेगी, हालांकि जीवाश्म ईंधन की कम कीमत एक निवारक के रूप में कार्य कर सकती है।
- तेल के उत्पादन और अन्वेषण में 10% निवेश बढ़ने की उम्मीद है। जीवाश्म ईंधन में इस विस्तार की योजना कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (Carbon Capture and Storage- CCS) तथा बायोएनर्जी (Bioenergy CCS) सीसीएस जैसी नई प्रौद्योगिकियों के साथ बनाई गई थी, जिन्हें अभी तक व्यावसायिक सफलता नहीं मिली है।
- **उत्सर्जन में वृद्धि:** उपरोक्त सकारात्मक परिदृश्य अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि को रोक नहीं पाएंगे, वर्ष 2020 में COVID-19 महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी के कारण। के कारण उत्सर्जन में संकुचन तो हुआ किन्तु ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि इस साल वैश्विक उत्सर्जन में 1.5 अरब टन की वृद्धि होगी।

3. नेट जीरो एमिशन की प्रगति संतोषजनक नहीं

- साल 2015 में पेरिस में जलवायु समझौता हुआ था। उसमें 2050 को ध्यान में रखते हुए उत्पादित ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas) उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है।
- अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को जीवाश्म ईंधनों की वजह से हो रहे कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा और इन ईंधनों का विकल्प भी तलाशना होगा। ये विकल्प ऐसे होंगे जो किसी तरह का प्रदूषण न फैलाएं। किन्तु कई विकासशील देशों की नीति नेट जीरो एमिशन (Net Zero Emission) के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।
- चीन कोयला आधारित बिजली उत्पादन में जबरदस्त विस्तार दिखा रहा है। दिसंबर 2020 में चीन की कोयले की खपत एक ऐतिहासिक उच्च स्तर पर थी, हालांकि चीन ने अक्षय ऊर्जा के विकास में सराहनीय विकास किया है।

5. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1973-74 में तेल संकट के कारण हुई थी।
- यह संगठन मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं।
- भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भी सदस्य नहीं है। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के तहत उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम के सदस्य के रूप में भारत इससे जुड़ा हुआ है।

4. विकसित राष्ट्रों की जिम्मेदारी

- इस रिपोर्ट के अनुसार उत्सर्जन को रोकने में विकसित राष्ट्रों की जिम्मेदारी-हिस्सेदारी को कम नहीं किया जाना चाहिए। विकसित देशों में उत्सर्जन की वृद्धि मध्यम है, लेकिन उनका निर्यात उत्सर्जन चिंता का विषय है। हाल के विश्लेषण के अनुसार, कोयले के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया का निर्यात उत्सर्जन घरेलू उत्सर्जन से दोगुना है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते में फिर से शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रति नई प्रतिबद्धता दिखाई है। लेकिन सस्ते शेल गैस के प्रति देश का आकर्षण निवेश में गड़बड़ी पैदा कर रहा है और भारत जैसे देशों के विकास पथ की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

06

चीन का कृत्रिम सूर्य

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चीन के 'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (Experimental Advanced Superconducting Tokamak-EAST) ने 20 सेकंड के लिए 288 मिलियन डिग्री फारेनहाइट का उच्चतम तापमान हासिल किया, जो सूर्य के तापमान से दस गुना अधिक है। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक से चीन को एक असीमित हरित ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगा।

2. प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक

- प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (ईएएसटी) रिएक्टर चीन के हेफेई में चीनी विज्ञान अकादमी (एएसआईपीपी) के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में स्थित एक उन्नत परमाणु संलयन प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है।
- चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2006 में की थी। चीन ने कृत्रिम सूरज को एचएल-2एम (HL-2M) नाम दिया है, इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के साथ साउथवेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है।
- EAST परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) का हिस्सा है, जो 2035 में चालू होने पर दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर बन जाएगा। इस परियोजना में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का योगदान शामिल है।

3. उद्देश्य

- इस कृत्रिम सूर्य का उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है, यह वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। इससे ईंधन के लिए चीन की दूसरे देशों पर निर्भरता और प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आने की उम्मीद है।

4. विशेषताएँ

- चीन के आर्टिफिशियल सूरज में लगे न्यूक्लियर फ्यूजन (Nuclear Fusion) रिएक्टर ने 100 सेकेंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया है। यह तापमान सूरज के तापमान से 10 गुने से भी काफी ज्यादा है।
- यह मशीन चीन की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक एटमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटर रिसर्च डिवाइस गर्म प्लाज्मा को संलयन के स्तर तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है।
- इस डिवाइस को कभी भी खत्म न होने वाली स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूरज और तारों के अंदर अपनेआप पैदा होने वाले परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी कारण यह डिवाइस 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करने में सक्षम हो पाई है।

5. फ्यूजन रिएक्शन

- न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स (ड्यूटीरियम और ट्राइटियम) आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा भी होने लगती है।
- ITER पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के शुरू होने में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पाद के तौर पर निकले।
- परमाणु हथियारों और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूजन की जगह फिजन (fission reaction) होता है। फ्यूजन रिएक्शन में किसी ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है और इसमें किसी ऐक्सिडेंट की संभावना या अटॉमिक मटीरियल की चोरी का खतरा नहीं होता है।
- बड़े स्तर पर अगर कार्बन-फ्री स्रोत के तौर पर यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है।

6. वैश्विक स्थिति

- चीन एक मात्र ऐसा देश नहीं है जहां ऐसी परियोजना चल रही है बल्कि फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसकी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है।
- वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य, कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च (केएसटीएआर) भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है।

07 मेगा फूड पार्क योजना

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।

2. प्रमुख बिन्दु

- मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा।
- यह पार्क लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और सीपीसी तथा पीपीसी जलग्रहण क्षेत्र में लगभग 25000 किसान लाभान्वित होंगे।
- खाद्य प्रसंस्करण के लिए लगाई गई आधुनिक अवसंरचना प्रसंस्कर्ताओं और छत्तीसगढ़ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को काफी लाभ पहुंचाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा।
- इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क में अत्याधुनिक अवसंरचना और विकसित प्रसंस्करण सुविधाएं न केवल कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करेंगी बल्कि मूल्यवर्धन भी सुनिश्चित करेंगी। यह पार्क किसानों, स्वयं सहायता समूहों तथा सूक्ष्म उद्यमियों को प्लग एंड ऑपरेट आधार पर प्रसंस्करण संचालन और पार्क के जलग्रहण क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगा।

3. मेगा फूड पार्क योजना के बारे में

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र तेजी से बढ़े और किसान की आय को दोगुना करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन जाए।
- जल्द खराब होने वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देने के साथ आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन और खाद्य अपव्यय को कम करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू कर रहा है।
- मेगा फूड पार्क, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करते हैं।
- केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाओं और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) और संग्रह केंद्र (सीसी) के रूप में फार्म के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाएं बनाई जाती हैं।
- इस योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

4. मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के बारे में

- मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.5 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है।
- पार्क में उद्यमियों के कार्यालय और अन्य उपयोग के लिए सामान्य प्रशासनिक भवन और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों में 03 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र भी हैं, जिसमें किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में खेतों के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा है।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. इंडिया इंडेक्स 2020-21

प्र. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये-

सूची-I (सतत विकास सूचकांक)	सूची-II (राज्य)
(a) केरल	1. द्वितीय स्थान
(b) हिमाचल प्रदेश	2. द्वितीय स्थान
(c) तमिलनाडु	3. प्रथम स्थान
(d) बिहार, झारखंड और असम	4. अंतिम स्थान

कूट:

	a	b	c	d
(A)	1	2	3	4
(B)	2	1	3	4
(C)	3	1	2	4
(D)	1	3	4	2

Ans: (C)

2. विश्व बैंक

प्र. ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. विश्व बैंक की इस शोध रिपोर्ट का शीर्षक "हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन" (Glaciers of the Himalayas, Climate Change, Black Carbon and Regional Resilience) है।
2. विश्व बैंक की शोध में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश (Himalaya, Karakoram and Hindu & Kush) पर्वत शृंखलाओं को शामिल किया गया है, जहां पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव देखा जा सकता है।
3. इन पर्वत शृंखलाओं में हिमनदों के पिघलने के गति, विश्व के औसत हिमक्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 3 (B) केवल 2 और 3
(C) 1 , 2 और 3 (D) केवल 1 और 2

Ans: (C)

3. LEO उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा

प्र. LEO प्रोद्योगिकी एवं सैटेलाइट इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. LEO उपग्रह 1990 के दशक से ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, ये कंपनियों और व्यक्तियों को विभिन्न संचार सेवाएं प्रदान करते हैं।
2. जियोस्टेशनरी उपग्रह धरती की भूमध्यरेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होते हैं।
3. चूंकि LEO उपग्रह पृथ्वी के करीब परिक्रमा करते हैं, इसलिए वे पारंपरिक स्थिर-उपग्रह प्रणालियों की तुलना में मजबूत सिग्नल और तीव्र गति प्रदान करने में सक्षम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 3 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) केवल 1 और 2

Ans: (C)

4. नासा द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले दो नए मिशन की घोषणा

प्र. नासा द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले दो नए मिशन की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दो नए मिशनों की घोषणा की है।
2. ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन 2030 से 2040 के बीच शुरू किए जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 नहीं 2

Ans: (A)

5. आठवां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन

प्र. आठवां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. आठवें 'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन' (International Nitrogen Initiative Conference- INI2020), का आयोजन जर्मनी में आभासी-प्रारूप में किया गया।
2. इस सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के 800 से अधिक वैज्ञानिक और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
3. अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल (INI) एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे 2010 में पर्यावरण की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति (SCOPE) और अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल-जैवमंडल कार्यक्रम (IGBP) के प्रयोजन के तहत स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही नहीं है / हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 3
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (C)

6. श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव

प्र. श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सिंगापुर के MVX -प्रेस पर्ल (MV X-Press Pearl) नामक मालवाहक जहाज में आग लगने और विस्फोट होने से श्रीलंका के समुद्र तटों पर कई टन प्लास्टिक के पैलेट (pellet) पाए गए।
2. प्लास्टिक कचरे से भरे जहाज के जलने के बाद उसके अवशेष बहकर उसके द्वीपों पर पहुंच रहे हैं और जल-जीवन के लिए खतरा बन गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 नहीं 2

Ans: (C)

7. मॉडल टेनेंसी एक्ट

प्र. मॉडल टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है।
2. इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।
3. मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) केवल 1 और 2

Ans: (C)

8. कोविड-19 का केवल डेल्टा वैरिएंट बेहद चिंताजनक: डब्ल्यूएचओ

प्र. कोविड-19 का केवल डेल्टा वैरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में पहली बार कोरोना के जिस प्रकार का पता चला था वो बी.1.167.2 था।
2. ये भारत में सबसे पहले पाए गए तीन में से एक उप-प्रकार है।
3. ये भारत में अक्टूबर 2020 में पाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1 , 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

9. अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

प्र. अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. एक राष्ट्र एक मानक की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसी संस्थान को एसडीओ की मान्यता दी जाती है।
2. इससे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत किया जा सकेगा। आरडीएसओ भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का एकमात्र संस्थान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

10. परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)

प्र. परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) के संदर्भ में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये-

सूची-I (ग्रेड)	सूची-II (राज्य)
(a) ग्रेड I++	1. गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, एनसीटी-दिल्ली, पुदुचेरी, राजस्थान दादर और नगर हवेली
(b) ग्रेड I+	2. पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल
(c) ग्रेड I	3. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और दमन व दीव
(d) ग्रेड II	4. गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्ष्यद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर

कूटः

	a	b	c	d
(A)	1	2	3	4
(B)	2	1	4	3
(C)	3	2	1	4
(D)	4	3	2	1

Ans: (B)

11. जी-7 देशों के बीच अहम समझौता

प्र. जी-7 देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जी-7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।
2. इसे ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) भी कहते हैं।
3. वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक जी-7 को जी-8 के रूप में जाना जाता था, किन्तु वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुनः जी-7 कहा जाने लगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

12. 24वां बिम्सटेक दिवस

प्र. हाल ही में 24वां बिम्सटेक दिवस (24th BIMSTEC Day) मनाया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसका पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल' 'निशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन' (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC) है।
2. बिम्सटेक (BIMSTEC) में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार सदस्य हैं।
3. बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation -BIMSTEC), बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और समीपवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय ढाका में अवस्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

13. ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ

प्र. ऑपरेशन ब्लू स्टार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस वर्ष ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ मनाई गई।
2. यह देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था।
3. भारतीय सेना की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर कि गई कार्यवाही को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

14. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

प्र. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2021-22 में खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

15. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

प्र. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।
2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

Ans: (C)

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

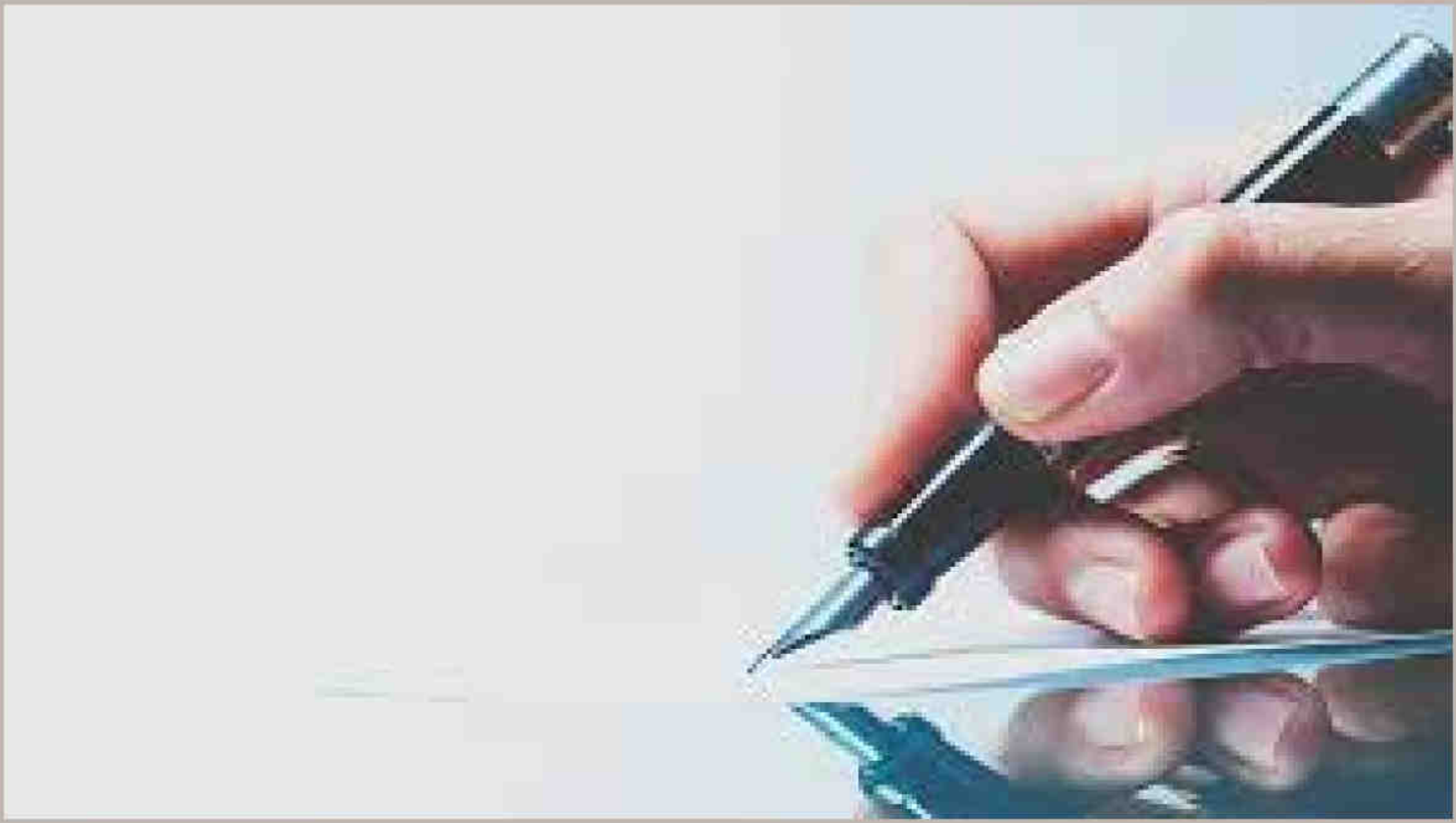

01

04

07

01 हाल ही में नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal -SDG) सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक पर विस्तार से चर्चा करें।

02 हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दो नए मिशनों की घोषणा की है। यह मिशन शुक्र ग्रह को जानने में किस प्रकार सहायक होगा?

03 हाल ही में आठवें 'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन' (International Nitrogen Initiative Conference- INI2020), का आयोजन जर्मनी में आभासी-प्रारूप में किया गया। यह सम्मेलन पर्यावरण सुरक्षा के लिए किस प्रकार सहायक है?

04 हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल किराएदारी अधिनियम (Model Tenancy Act) के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम किस प्रकार किरायादारों के हित में है?

05 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि भारत में पाए गए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट B.1.617 का केवल एक स्ट्रेन B.1.617.2 ही अब 'चिंता का सबब' है। डेल्टा वेरिएंट पर प्रकाश डालें।

06 हाल ही में जी-7 के देशों के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। इस समझौते से प्रौद्योगिकी कंपनियों को उचित कर का भुगतान करना होगा। जी-7 के संधर्भ में इस समझौते की आवश्यकता को बतायें।

07 हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ मनाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर विस्तार से चर्चा करें।

08 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने मौद्रिक नीति (Monetary Policy) जारी की है। यह मौद्रिक नीति भारतीय अर्थ्यव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगी?

09 हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index- PGI) 2019-20 जारी की है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में विभिन्न राज्यो की स्थिति का उल्लेख करें।

10 भारतीय रेलवे के अनुसंधान में मुख्य भूमिका निभाने वाला अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन (आरडीएसओ) 'एक राष्ट्र एक मानक' अभियान के तहत ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड्स (बीआईएस) का पहला मानक विकास संगठन (एसडीओ) संस्थान बन गया है। "एक राष्ट्र एक मानक अभियान" के बारे मे विस्तार से बतायें।

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

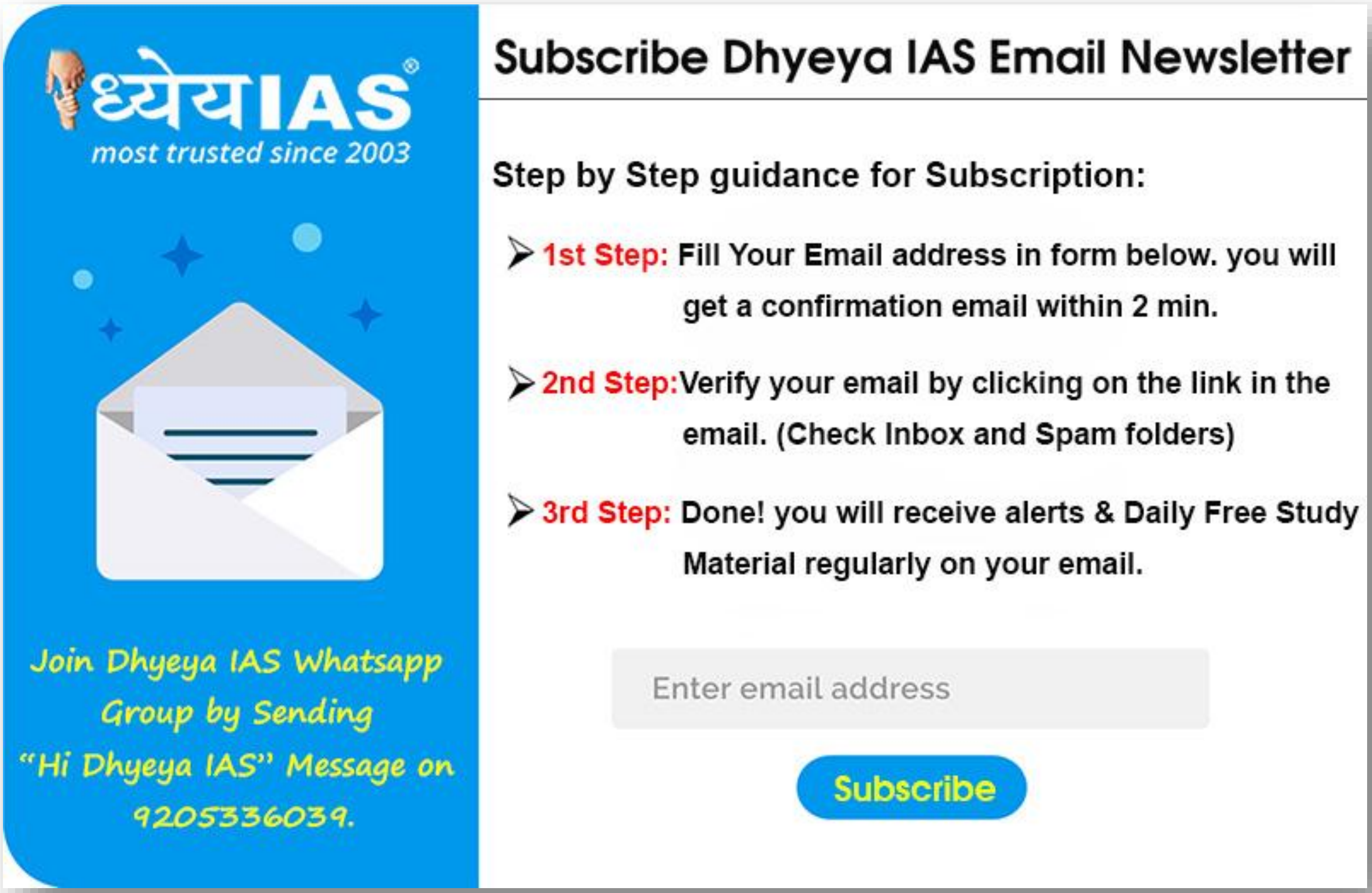

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com